डा० बापू कालदाते : उपसभाध्यक्ष, महोदय आपने प्रार्थना की है और कुछ समय मांगा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि मंत्री महोदय कितना समय लेना चाहते हैं, यह बता दें। यह अच्छा रहेगा कि यह बता दिया जाये कि इसके बारे में कब चर्चा होगी।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Can you give some indication?

SHRI BINDESHWARI DUBEY: I cannot precisely assure the House about the timing. I have just got it. I will have to look into it, examine it and go to the Cabinet again. So, I cannot give the exact date.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Not the exact date but some indication. I mean after one week or so.

SHRI BINDESHWARI DUBEY: During this Session, certainly.

STATEMENT BY MINISTER

Reg. Flood situation in the country

कृषि मंत्री (श्री भजन लाल) : महोदय मैं बाढ़ की वर्तमान स्थिति और प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिये सरकार द्वारा उठाये गये कदमों के बारे में एक वक्तव्य देने के लिए सदन की आज्ञा चाहता हूं। मुझे इस बात का पूरा अहसास है कि भारी वर्षा और अचानक बाढ़ आने से लोगों को हुई कठिनाइयों के बारे में माननीय सदस्यों को चिन्ता है।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मौसमी पूर्वानुमान के अनुसार यह आशा थी कि दक्षिण-पश्चिमी मानसून जून से सितम्बर, 1989 के दौरान वर्षा सामान्य के मुकाबले 102 प्रतिशत होगी तथा इसमें 4 प्रतिशत का अन्तर हो सकता है। जून, 1989 के अंत तक देश भर में कुल वर्षा सामान्य के 106 प्रतिशत के बराबर रही हालांकि उत्तर पश्चिमी भारत में कुछ कमी रही। 19 जुलाई को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान 35 मौसम वैज्ञानिक उप प्रभागों में से 27 में अधिक या सामान्य वर्षा हुई और इस अवधि के दौरान देश के 67 प्रतिशत जिलों में अधिक या सामान्य वर्षा हुई।

लेकिन पिछले कुछ दिनों में देश के अधिकतर भागों में वर्षा में निश्चित वृद्धि हुई है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पश्चिमी भाग में कम दबाव का एक निश्चित क्षेत्र बना हुआ था जो 22 जुलाई की शाम तक अधिक दबाव वाला क्षेत्र बन चुका था और 23 जुलाई की सुबह तक यह कलिंगापट्नम में आन्ध्र प्रदेश के उत्तरी तटवर्ती भाग को पार कर चुका था। पश्चिमी-उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ते हुए यह 25 जुलाई, 1989 को मोन्ट आबू के निकट पहुंच गया। इसके उत्तर पश्चिमी दिशा में और आगे बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और कुछ हद तक उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में दूर-दूर तक वर्षा हुई है। भूमि वाले क्षेत्र में इसके और आगे बढ़ने से गुजरात तथा राजस्थान में भी अधिक वर्षा हुई है।

महाराष्ट्र में मराठवाड़ा और कोंकन क्षेत्रों के चौदह जिलों में भारी वर्षा होने की सूचना मिली है। पुणे और बम्बई के बीच रेल की पटरियों के कुछ भागों में दरार पड़ने से क्षति पहुंची है जिससे संचार व्यवस्था में बाधा पड़ गई है। भारी वर्षा के साथ-साथ प्रति घंटा 70-80 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाएं भी चली थीं जिससे सार्वजनिक सम्पति को भी नुकसान पहुंचा है। कल अर्धरात्रि तक प्राप्त सूचना के अनुसार महाराष्ट्र में 332 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

आन्ध्र प्रदेश में 13 जिले जिनमें पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा और गुन्टूर के 4 तटवर्ती जिले भी शामिल हैं, भारी वर्षा से प्रभावित हुए हैं। इस क्षेत्र में 23.7.1989 को 20 से.मी. तक वर्षा हुई है और बाढ़ें भी आई हैं। कृष्णा और पश्चिमी गोदावरी जिलों में बदमेरु, तमिलेरु आदि जैसी नदियों में

[श्री भजन लाल]

तेज और अचानक बाढ़ें आई हैं। इससे कुछ कस्बे भी बाढ़ ग्रस्त हो गए हैं। पश्चिमी गोदावरी का एलुरु मुख्यालय का शहर 3 फुट जल में डूब गया है। इस राज्य में अभी तक मिली सूचना के अनुसार बांढ़ और भारी वर्षा के कारण 124 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है।

इन जिलों और निजामाबाद में फसलों को भारी हानि पहुंचने की खबर मिली है। राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों के दलों का गठन किया जा चुका है जो क्षति का मूल्यांकन और अपेक्षित राहत उपायों का जायजा लेने के लिए प्रभावित क्षेत्रों में कल चले गए हैं।

केरल में पिछले कुछ दिनों के दौरान हुई भारी वर्षा के परिणामस्वरूप कोट्टायम इदुकी, एलिप्पी, पालघाट, पाथानामथिटा और वेनाड़ जिलों में काफी क्षति हुई है इदुकी जिले में बहुत से लैण्ड-एलाईडस के कारण 21 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और 4000 मकान क्षतिग्रस्त हो गए, जिनमें से 1500 मकान पूर्णतया क्षतिग्रस्त हुए हैं और 2500 मकान आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए है।

बताया गया है कि कर्नाटक में भी अधिकतर नदियों में बाढ़ आई हुई है। इस संबंध में सही ब्यौरों की प्रतीक्षा है।

तमिलनाडु में, पिछले कुछ दिनों के दौरान व्यापक वर्षा हुई है परन्तु क्षति के बारे में अभी राज्य सरकार से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। गुजरात के जिला वलसाद में नवसारी शहर में भी कुछ निचले इलाकों से बाढ़ के कारण कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है।

भारी वर्षा और बाढ़ के फलस्वरूप संचार व्यवस्था में रुकावट आई है। विजयवाडा और काजीपेट के बीच हसनपरती, गारला, मोटुम्मरी में और विजयवाड़ा के निकट भी दरार पड़ने के कारण रेल की कुछ पटरियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। विजयवाड़ा और वाल्टेयर के बीच एलुरु और देन्दलुरु के पास रेल की पटरियों को नुकसान पहुंचा है। पूना-बम्बई क्षेत्र में भी लोनावाला के पास रेल की पटरियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। यह आशा की जाती है कि विजयवाड़ा-कार्जपेट पटरियां शीघ्र ही ठीक कर दी जाएंगी और विजयवाड़ा तथा वाल्टेयर और बम्बई तथा पुणो के बीच रेल की पटरियों को पुनः ठीक करने में अभी कुछ और समय लगेगा।

सड़क मार्ग से संचार व्यवस्था में रुकावट आने और बिजली जैसे बुनियादी ढांचे को क्षति पहुंचाने की सूचना भी मिली है।

राज्य सरकार द्वारा पूरा मूल्यांकन अभी किया जाना है तथा और अधिक ब्यौरों की प्रतीक्षा की जा रही है।

जहां कहीं राज्य सरकारों ने मांग की वहां सेना, नौ-सेना और वायु-सेना की सहायता सुलभ कराई गई है। राज्य सरकारों ने राहत शिविर भी खोल दिए हैं और दल गठित करने के लिए तथा अस्थायी आवास स्वास्थ्य सुविधाओं आदि जैसी सुविधाएं देने के लिए कार्यवाही की जा रही है।

उत्तर-पूर्वी राज्यों में असम और अरुणाचल प्रदेश में जहां जून के मध्य में भारी वर्षा हुई थी और जमीन खिसक गई थी, अब स्थिति सुधर रही है, हालांकि जल-ग्रहण क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण कुछेक नदियां अब भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उत्तर प्रदेश के 6 जिलों और बिहार के 2 जिलों से भी बाढ़ से नुकसान होने की सूचना मिली है।

वर्तमान वर्षा ऋतु में अब तक आन्ध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार,

केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व कर्नाटक राज्य बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। मुझे यह बताते हुए हार्दिक दुःख हो रहा है कि अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 124, अरुणाचल प्रदेश में 24, असम में 4, केरल में 65, महाराष्ट्र में 332 और उत्तर प्रदेश में 37; अर्थात् कुल 586 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में कुछ मछुआरों के लापता होने की खबर भी है जिसके विषय में सही विवरण प्राप्त किया जा रहा है।

प्रभावित राज्यों को आपातिक राहत उपाय करने के लिये 204.25 करोड़ रुपये की मार्जिन धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। इन्हें निर्देश दिया जा चुका है कि ये जहां जरूरत हो वहां पैसा खर्च करके लोगों को राहत दें। जिन लोगों की बाढ़ के कारण मृत्यु हुई है उनके परिवारों को प्रधान मंत्री जी अपने राहत कोष से 10000 रुपये प्रति परिवार की दर से सहायता दे रहे हैं। भारत सरकार स्थिति पर कड़ी निगाह रखे हुए है और कृषि और सहकारिता विभाग का आपत्ति प्रबंध दल स्थिति का जायजा लेने के लिए लगातार अपनी बैठकें कर रहा है ताकि बिना समय नष्ट किए राहत पहुंचाई जा सके। मैं सदन को आश्वासन देना चाहूंगा कि राज्य सरकारों से केन्द्रीय सहायता के लिए ज्ञापन जैसे ही प्राप्त होंगे उन पर सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही करके राज्यों को हर संभव सहायता दी जायेगी, जैसाकि हम हमेशा देते रहे हैं।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): There are 16 Members who want to seek clarifications. I would request you all to be as brief as possible.

श्री नरेश सी० पुगलिया (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, इस माह की 24 तारीख को अपने देश के अन्दर कुछ राज्यों में भारी मात्रा में बाढ़ आई है। उसके कारण जो हानि हुई है इसमें खास कर के महाराष्ट्र और साउथ की तीन चार स्टेट्स प्रभावित हुई हैं और अगर कहीं सबसे ज्यादा हानि हुई है तो वह महाराष्ट्र में हुई है। मंत्री महोदय ने अभी जो आंकड़े दिये हैं जिसमें यह कहा गया है कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में 332 लोगों की मृत्यु हुई है और कुल 550 लोग की मृत्यु हुई है। यह आंकड़े सरकार ने उपलब्ध कराए हैं लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से अकेले महाराष्ट्र में ही 550 से ज्यादा लाशें अभी तक बरामद हो चुकी हैं और दो हजार लोग लापता हैं जिसमें एक हजार के करीब मछुआरे हैं। महाराष्ट्र के अन्दर 14 जिलों में फसल पूरी तरह चौपट हो चुकी है और हजारों जानवर इस पानी के अन्दर नदियों में बह चुके हैं। करोड़ों रुपयों की हानि किसान भाइयों की हुई है और रेल सेवा, बस सेवा, टेलीफोन सेवा, यह सभी सेवाएं इससे प्रभावित हुई हैं। 24 तारीख के दिन...

श्री भजन लाल: वाइस चेयरमन साहब, मैं आप से एक अर्ज करना चाहता हूं। अभी सही और पूरे आंकड़े आए नहीं हैं अगर आपकी इजाजत हो तो इस विषय पर पूरी डिसकशन सोमवार को आप रख दें जब तक पूरे आंकड़े भी आ जाएंगे कि कहां-कहां कितना नुकसान हुआ है (व्यवधान) हमें तो कोई एतराज नहीं है लेकिन पूरी जानकारी सब को तब मिल जाती।

श्री चतुरानन मिश्र (बिहार): आप तो जब चाहें मोशन ला दीजिये डिबेट हो जाएगा। (व्यवधान) बाढ़ लाना जितना आसान है, यह उससे भी ज्यादा आसान है मोशन लाना (व्यवधान)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): If necessary you can bring another statement. But today the Members are prepared and anxious to ask their questions.

भजन लाल जी आज कुछ लोग सजेश्चन देंगे उनको नोट करके आप

[Vice-Chairman]

कार्यवाही कर सकते हैं । इसलिए आज यह जरूरी है ।

श्री नरेश सी० पुगलिया : मंत्री महोदय की इस बात से मैं सहमत हूं कि पूरे आंकड़े आज उपलब्ध नहीं हो सकते हैं (व्यवधान)

SHRI ARANGIL SREEDHARAN (Kerala): I am on a point of order. The Minister said he did not have full and exact figures. That means by giving these figures here he is misleading the House.

श्री भजन लाल : मैंने यह नहीं कहा कि आंकड़े नहीं हैं । मैंने कहा कि माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी नहीं है । जब तक शनिवार और रविवार को वे अपने एरियाज में जाएंगे और आंकड़े लेकर कुछ बात कह सकेंगे । मैं तो आपकी मदद के लिए कह रहा हूं । हमारे पास सब आंकड़े मौजूद हैं । जो आप पूछना चाहते हैं पूछिये ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देशाई) : नो प्वाइंट आफ आर्डर ।

श्री नरेश सी० पुगलिया : जो 14 जिले महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उनमें चार जिलों में खास कर के पूना, कोल्हापुर, नांदेड़ और बीर में चार सैनिक जवानों की मदद ली गई है । वहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आर्मी, नेवी और एअर-फोर्स के तीनों विंग्ज को लगा कर वहां की जनता के लिए फूड पेकेट्स गिरा कर तथा उनको बाहर निकालने के सब काम जो केन्द्रीय सरकार ने किये हैं इनके लिए मैं उनका तहेदिल से शुक्रिया अदा करता हूं । यह उनका फर्ज भी था राज्य सरकार द्वारा मदद मांगने पर उसकी मदद करना और केन्द्रीय सरकार ने तुरन्त मदद की है । इसके इलावा जो भारी मात्रा में हानि हुई है खास करके जो लोनावाला एक्सप्रेस थी उसके दो डिब्बे नदी में गिरने से काफी लोग मारे गये । उसमें अभी 8–10 लाशें बरामद हो सकी हैं काफी लोग लापता हैं । उसमें डेढ़ सौ के करीब लोगों के मारे जाने की आशंका है । इसके इलावा रायगढ़ जिले में 198 लोगों की लाशें मिली हैं । काफी लोग उस में बह गये हैं । पातालगंगा और अम्बा नदियों में काफी बड़ी मात्रा में बाढ़ आने की वजह से 20 से अधिक विलेजेज के लोग प्रभावित हुए हैं । हजारों जानवर भी प्रभावित हुए हैं । इसके अलावा दूसरा जो मराड़वाड़ा का भीड़ जिला है, यह सब से ज्यादा प्रभावित हुआ है । उसमें 54 लाशें बरामद हुई हैं और वहां का अंदाज है कि 200 से ज्यादा लोग वहां बह चुके हैं, क्योंकि अचानक रात में बाढ़ आ जाने की वजह से लोगों को उसका अंदाज नहीं था और उसमें बड़ी मात्रा में मनुष्यों की हानि और जानवरों की भी हानि हुई है और मराड़वाड़ा के तीन-चार जिलों में फसल एकदम बह गई है, चौपट हो गई है ।

इसके अलावा जितनी भी क्राप्स को डैमेज हुआ है, उसको पूरा करने के लिए मैं माननीय कृषि मंत्री जी से अपील करूंगा कि आप अपनी केन्द्र सरकार की सर्वे टीम महाराष्ट्र में भेजें और साउथ के जो अन्य प्रांत हैं, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, वहां पर भी भेजें, लेकिन जो सबसे बड़ी हानि महाराष्ट्र में हुई है, इसमें आप तुरन्त मदद करें क्योंकि राज्य सरकार के बस की यह बात नहीं है ।

इतने बड़े पैमाने पर हानि होने की वजह से जब तक कि केन्द्र अपनी टीम इमिजेट्ली नहीं भेजता, उसका सर्वे नहीं करता, उन्हें बीज और दूसरे सामान जो भी लगता है, यदि वह उसे उपलब्ध नहीं है, तो उसके अभाव में वहां के किसान दूसरी फसल के लिए तैयारी नहीं कर सकेंगे ।

मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे कृषि मंत्री, भजन लाल जी जिस प्रकार से तत्परता से कृषि मंत्रालय चला रहे हैं, उसी तत्परता से महाराष्ट्र में जो हानि हुई है, उसका ...(व्यवधान) बापू कालदाते जी, यह कोई हंसने वाली बात नहीं है । जो सच्चाई है, उसे सच्चाई समझें ।

तो इसमें आप कृषि मंत्रालय के हिसाब से वहां के किसानों की पूरी मदद करें और खास करके प्रधान मंत्री जी ने—जिनकी जानें गई हैं उनकी जानें तो वापिस आ नहीं सकतीं, लेकिन उनके परिवार को प्रधान मंत्री कोष में से जो दस-दस हजार रुपये देने की अनाऊंसमेंट की है, उसके साथ राज्य सरकार भी उनकी कुछ मदद करे—यह अपेक्षा हम रखते हैं। इन पांच-छह स्टेट्स में जो बड़ी हानि हुई है, उसको देखते हुए और खास करके 24 जुलाई का दिन यह हिन्दुस्तान के इतिहास में एक बहुत बुरा दिन है। उस दिन लोकतंत्र की भी बहुत बड़ी हत्या हुई। जिस प्रकार से बाढ़ से देश के कोने-कोने में हमारे...(व्यवधान)

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY (Andhra Pradesh): That was a historic day when the Opposition had taken a decision for the sake of democracy.

श्री नरेश सी० पुगलिया : हम अपने विचार रखे हैं। जिस जनता ने आपको चुन कर यहां भेजा, उससे पूछे बगैर आपने रिजाईन किया, उसको लेकर यही कहा जाएगा और क्या कहा जाएगा।

तो इसलिए 24 जुलाई का दिन भारतवर्ष के लिए बहुत बड़ा ... (व्यवधान)

श्री चतुरानन मिश्र : माननीय सदस्य सदन में ऐसी बात न कहें, नहीं तो फिर दुबारा सदन में तूफान आ जाएगा।... (व्यवधान)

SHRI M. A. BABY (Kerala): Will you permit us to talk about the flood of corruption?... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): This is a very serious matter. All are concerned about it. I think you should not talk about other things here.

श्री नरेश सी० पुगलिया : उपसभापति महोदय, मैं फिर कृषि मंत्री जी से विनती करूंगा कि वह अपनी टीम जल्द से जल्द भेज कर जिन राज्यों में ज्यादा से ज्यादा नुकसान हुआ है और खास करके महाराष्ट्र में जो, इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है, वहां अपनी टीम तुरन्त भेजें और वहां के किसानों की पूरी मदद करें।

हम उम्मीद करते हैं कि केन्द्र सरकार ने जो भी मदद की है, सैनिक सहायता दी है, हेलीकोप्टर दिये हैं, उसी प्रकार से कृषि के क्षेत्र में भी पूरी मदद करेगी।

जिनकी जानें गई हैं और खास करके जो एक हजार मछुआरे लापता हैं बम्बई के समुद्र में और उसके किनारे के तीन चार डिस्ट्रिक्स में, उनको ढूंढने के लिए भी नेवी पूरी मदद कर रही है।

हम उम्मीद करते हैं कि कृषि मंत्रालय जल्द से जल्द अपनी टीम को महाराष्ट्र में भेज कर वहां के किसानों की पूरी मदद करेगा।

धन्यवाद।

कुमारी सईदा खातून (मध्य प्रदेश) : जो पुगलिया जी ने कहा है, मैं भी अपने आपको इससे संबद्ध करती हूं।

SHRI M. S. GURUPADASWAMY (Karnataka): Mr. Vice-Chairman, Sir, the havoc caused by the storm, rain and floods during the current rainy season came rather very suddenly. As a result of the storm, rain and floods, hundreds of people have died. The Minister has given, according to me, a lower figure. Anyway, we will wait. Many people have died. Crops have been damaged. Houses have been uprooted. Cattle have been washed away. All these have caused great distress in many areas of the country. In particular, Sir, the Minister has pinpointed a few States where the damage has been very severe. Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Assam, Bihar, Kerala, Maharashtra, Uttar Pradesh and Karnataka have been specifically named. There may be other areas in future. What I am concerned with is how the Government reacts to such situations.

[Shri M. S. Gurupadaswamy]

In the statement, in the last para, which is the operative para, the Minister has stated that some relief has been provided from the Prime Minister's Fund. Very good. And it is also said that some margin money is there with all the States, amounting to a certain figure, that can be utilized. But it goes on to say that the Crisis Management Group in his Ministry is watching at Delhi. I will read out:

"The Government of India is also keeping a close watch over the situation and the Crisis Management Group in the Department of Agriculture and Cooperation is meeting regularly to take stock of the situation and extend the relief without loss of time..."

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): But some teams have been sent.

SHRI M. S. GURUPADASWAMY: I do not know. If it is so, I am happy. But it is not here. I want the very thing that you are suggesting. This Crisis Management Team should go to areas where the damage has been caused and assess themselves. Government should not wait for memoranda to be sent by State Governments, and this official team should be sent for assessment of damage and for rendering relief. This type of bureaucratic approach will not do. The Crisis Management Team should be in the area of the crisis where damages have occurred and they have to have a quick assessment and all help should be rendered—material, financial and otherwise. This is not being done. It is the same routine way. The matter is handled. And the statement is written by the bureaucrats, I know. The Minister has read out the statement here. I would like the Minister to take the initiative in his own hands and ask the officials in his Department to go. Why are they sitting here?

Secondly, Sir, I would like the financial assistance to be released quickly without waiting for the memoranda to come from various States. There could be a procedure. That bottleneck should be overlooked because the crisis is too great. Therefore, give up the old procedure and give the sanction immediately.

In my State there has been a havoc. The Minister does not have the full information. He is waiting for the information. Even there a lot of damage has been caused in certain areas of Karnataka. Since I come from Karnataka, I would say that the Minister should sanction immediately, at least Rs. 50 crores, apart from what is available with the State Government—Rs. 50 crores from hereso that relief work can be taken up adequately, quickly and satisfactorily. That applies to other States also. The havoc is great in Maharashtra. It is very great in Andhra Pradesh. I would like the Minister to take the House into confidence as and when he gets information regarding the havoc caused due to these heavy rainfalls. When he makes his next statement on Monday or later, I would like him to make a comprehensive statement. I would also expect him to tell us what concrete measure he is going to take and what concrete help he is going to give to the State Governments in this regard.

SHRI B. SATYANARAYAN REDDY: Mr. Vice-Chairman, Sir, a grave and serious situation has arisen due to unprecedented floods in different parts of the country, especially in the States of Andhra Pradesh, Maharashtra, Karnataka, Kerala and some parts of Orissa, Uttar Pradesh and other parts of the country. This has been our experience in the past that whenever natural calamities such as floods occur in different parts of the country and whenever the Central Government appointed a committee to go into the losses and suffering of

the people in those areas, the action was very slow. The team used to visit the States after a month or two. So, I want to say that action must be immediate and relief must be immediate.

The hon. Minister has stated in the statement that due to heavy rains there has been heavy loss of life and property in different States of the country. The margin money that has been shown is very meagre. I do not know how the States are going to meet the expenses on relief that is to be given to the people out of this meagre amount of margin money. It is about 204 crores of rupees. It is only a drop in the ocean. I request the hon. Minister that this margin money should be increased and a larger amount should be placed at the disposal of the States to meet the urgent requirements of relief work.

It is really the people who suffer and those people are poorer sections of the society. They are agriculturists, farmers, labourers, hut dwellers, etc. These are the people who have been affected. So, the Government must take immediate action in providing relief and in rushing money to the affected areas so that people may get timely relief. As my friend has said, irrespective of the fact that whether it is Maharashtra, Karnataka, Andhra Pradesh or any other State, all should be given help immediately. So far as Andhra Pradesh is concerned, I would like to draw the attention of the hon. Minister to the fact that due to heavy rains, many districts have been affected. As the hon. Minister said in his statement, in Andhra Pradesh 13 districts and especially the coastal districts, namely, Cuddapah, East and West Godavari, Krishna, Guntur, Khamam, Nizamabad, Medak and Warangal, have been worst affected. The Minister has omitted to mention some of the districts. I may tell him that the districts which I have named are worst affected. There has been a great loss of life and property. Our Chief Minister, Shri N. T. Rama Rao, has immediately rushed to the affected areas, inspected the areas and instructed the officials to take and provide immediate relief measures. But, at the same time I want that the Central Government also should bear its responsibility and they must provide immediate relief that is needed for the people. As I stated earlier, the Central team should be sent immediately to these affected areas so that they may have a correct assessment of the loss of life and property. Secondly, Sir, we also want that Naval boats should be supplied because the whole area is flooded with water. So, Naval boats should be immediately supplied to the affected areas, specially to Andhra Pradesh. The State Government has demanded this. Thirdly, Sir, there should be financial aid provided immediately. Sir, it has always been the experience of many States and that of Andhra Pradesh also that whenever financial help is needed or sought, only one-fourth of the amount sought for is provided. If Rs. 200 crores are needed, only Rs. 20 or Rs. 30 crores are provided. I request the Minister that whenever a State demands any relief, if they send any report of the loss or the damage that has been caused due to floods, full amount of the financial assistance sought for should be given. These are the essential things and I request the Government to take these immediate steps. और मैं जानता हूं कि भजन लाल जी तो किसानों की समस्याओं को कुछ समझते हैं और खासकर बाढ़ वगैरह जब आती है तो उसमें मुसीबतदां लोग अधिकतर किसान ही होते हैं। उनके खेत नष्ट हो जाते हैं, उनके मवेशी नष्ट हो जाते हैं। उनका बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए उनको मदद पहुंचाने में किसी किस्म की देरी नहीं होनी चाहिएं। इमीडियेट रिलीफ वर्क्स शुरू होने चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं। इसमें आप यह न

[श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी]

देखें कि वहां से रिपोर्ट्स आएंगी कि कितना नुकसान हुआ है और उस पर आप तय करेंगे। ऐसा सोचकर आप न बैठें और सेंट्रल टीम भेज दी जानी चाहिए इमीडियेट फायनेंसियल हैल्प जो भी हो सकती है, उसे जल्द-से-जल्द भिजवाएं। महोदय मैंने तीन चीजों की मांग की है— एक इमीडियेट फायनेंशियल रिलीफ, दूसरे केन्द्रीय बाढ़ सहायता किए जाएं और तीसरे सेंट्रल टीम इमीडियेटली भेजी जायें। मैं चाहूंगा कि इन तीनों मुद्दों पर आप जल्द-से-जल्द कदम उठाएं। धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now the list before me is very big. So many names have been added. Now it has become 20. It is very difficult for me also to....

डा० बापू कालदाते (महाराष्ट्र): मैं तो पहले भी एसोसिएट करना चाहता था।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I will try to accommodate as many as possible.

SHRI A. G. KULKARNI (Maharashtra): My name was the first actually.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr Kulkarni, no doubt your name is there. I cannot allow more than 4 from the Congress-I side. I cannot accommodate all. Your name is there.

SHRI A. G. KULKARNI: I have got a meeting....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I will give you time definitely.

SHRI P. K. KUNJACHEN (Kerala): Sir, the Minister has stated....

श्री रामचन्द्र विकल (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, स्पेशल मेंशन के वक्त मुझे कहा गया था कि आप जरूर बोलेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I will accommodate as many as possible.

SHRI P. K. KUNJACHEN: Sir, the Minister has stated that 65 persons have died in Kerala due to floods. But the problem is very wide. He has mentioned about the houses destroyed and the damage caused. It is only the tip of an iceberg. Sir, huge damage has been caused in our State. More than half of the districts of Kerala are very badly affected. These are Idduki, Kottayam, Calicut, Allepey, Pathanam Thitta, Paleghat etc.

Sir, more than half of the districts have been affected by these huge floods and a vast damage has been caused. The Government here has stated that some amount has been entrusted to the State Government to be spent as margin money etc. But the thing is that when such calamities come, the Government here is not acting speedily to find a solution. Therefore, I request the Minister to see that relief is provided immediately at least before the next drought comes. I am telling this because of the experience in Kerala. Last time when there was a huge drought the Government at that time applied for Rs. 57 crores. Again a further calculation was made and an additional Rs. 12 crores were requested, but recently they have given only Rs. 5 crores. The team had gone there, conducted an inquiry etc. and now again the flood season has come and huge damage has been caused and team is sitting here and watching the situation from here. I completely agree with Shri Gurupadaswamy, when he asked what is the duty that these teams have to perform in such a serious situation? In such situations, the teams must tour. They have got the Government aeroplanes and helicopters. Why can't these be used? When such floods come, these teams must immediately rush to the States,

study the situation and render whatever help they can. That should be the attitude. But here the Government is taking a very complacent attitude and watching the situation from Delhi only. This attitude must go and immediately help should be given to protect the people. That is what I want to say. Sir, with these words, I conclude. Thank you.

श्री राम अवधेश सिंह : मान्यवर . . . (व्यवधान) . . .

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : आपका काम मैंने लिख लिया है । . . . (व्यवधान) . . .

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Yes, yours will be the 21st name.

SHRI A. G. KULKARNI: Sir, I am first obliged to you for calling my name, at least.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): No, there is no obligation. Your name is there.

SHRI A. K. KULKARNI: I am obliged to you anyway, because we have to take your help. Otherwise, it is not possible.

Sir, I draw the attention of the Minister to the very devastating floods all over the country. Out of that, Maharashtra is affected to a very large extent. Sir, the information supplied to us by the State Government says that they are about 332 dead, which has come in your statement also. But knowledgeable persons from that area, Marathwada etc. say that it has gone to 500 or even 700. So, that is the situation and the number has substantially increased. Still efforts are being made to locate the bodies. That search is going on.

Mr. Vice-Chairman, Sir, I am aware, and I am not going to plead with you like my friend, because I know that the Central Government and particularly the Prime Minister has sanctioned a munificent grant to the kith and kin of the dead. Whether it will be enough or not, it will be seen and it can be increased at a later stage.

Sir, I am aware that the Central Government has sanctioned or rather placed at the disposal of the State Governments a sum of Rs. 343 crores as margin money for further relief. That also will be very useful at the present moment. The Chief Minister of Maharashtra has called a meeting, as you have stated, only yesterday, of all the Secretaries, Army, Naval, Railway and Airline officials and maximum support to the people in this tragic condition is already being given. But the Prime Minister and the Minister of Agriculture who are looking after these matters, have to immediately take following measures. Mr. Bhajan Lalji, what you have to find out from your counterpart, Mr. Sukh Ram is, whether food is being immediately rushed to these areas and items like rice, sugar, wheat, because these devastating floods have submerged villages and, therefore, food has to be rushed immediately to these areas. I would request you to take special efforts to rush food there. Secondly naval assistance particularly to the marooned villages which have been so much flooded, is to be arranged immediately. Then, Sir, your assessment teams have to rush to those areas. It is an all India problem. There are many States which have been affected. Therefore, assistance has to be provided to them. Unfortunately, this time Maharashtra is the worst affected State otherwise, it is usually Andhra and Karnataka on this side and some northern States on the other. As my friend is suggesting, besides food fodder is also an essential item which is in very short supply, and it has to be rushed there. I understand that about Rs. 13 crores have been allotted to Maharashtra. I would suggest that at least another Rs. 50 crores should be placed at the disposal of the Government of Maharashtra; otherwise

[Shri A. G. Kulkarni]

it will be a very difficult situation because as you know, Maharashtra is facing many problems with regard to finances, because of non-renewal of loans to the farmers. Of course now they have started it. So, this special aspect of Maharashtra should be taken into consideration. There is no use repeating the same points raised by my friends already. I would only request you, Mr. Minister, to consider these problems and take immediate action.

SHRI CHITTA BASU (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, I shall not take more than 3 or 4 minutes; I take note of it. I woud be very specific.

I refer to the hon. Minister's statement, paragraphs 8 and 9. From paragraph 8 of the statement, it is found that eight States in the country have been affected by floods. So far as the past experience is concerned, 11 these eight States are generally flood-prone. In this connection, may I know from the hon. Minister whether he will clarify as to what flood control measures have been taken with regard to these eight States, which are generally flood-prone, in the year 1988-89. This point needs to be clarified.

The second point I would like to make is in regard to paragraph 9 of the statement. For the eight States which are reeling under floods, the margin money so far provided comes to Rs. 204 crores only. You can have a quick calculation. The provision of margin money for these eight States is only Rs. 204 crores. I hope the hon. Minister will take this into consideration. I hope he realises that with this meagre provision of Rs. 204 crores, these eight States cannot meet the situation so far as relief operations are concerned. Therefore, I would like to know, what steps the Govenment propose to take to augment the financial resources of these affected States. In this connection may I draw the attention of the hon. Minister that on previous occasions, whenever such natural calamities took place, there has been a demand from all sections of the House that there should be a Fund, a National Calamity Relief Fund or a National Disaster Relief Fund? Why such a kind of fund has not been created so far which would have enabled these States, the affected States to get money from this Fund, which would enable them to meet the immediate requirements when such natural calamities like floods or drought or any other thing occur? Therefore, I want to be informed, what steps have so far been taken in regard to this proposal of creating a special Fund to meet the situation arising out of such natural calamities.

Sir, there has been a persistent complaint that even in the matter of allocation of foodgrains for flood relief etc., the non-Congress (I) Governments are discriminated against. This is the complaint. Would I be assured by the hon. Minister that the three non-Congress (I) States which have been affected, namely, Kerala, Andhra Pradesn and Karnataka...

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO (Andhra Pradesh): Karnataka is under President's Rule.

AN HON. MEMBER: Assam is also there.

SHRI CHITTA BASU: Yes, Assam is also there. In regard to Karnataka, I still consider that the majority is there. Anyway, would the hon. Minister give this categorical assurance that no discrimination would be made against the non-Congress (I) States which are reeling under floods?

I am concluding. Then, Sir, it has been our very sordid experience. The State Governments submit reports. You know the procedure. It has been the invariable response from the Government of India that the claims are inflated and, therefore, they cannot meet the requirements and that the

statemens given by the State Governments are not correct on the basis of the ground realities. This has been the general nature of reply or response from the Central Government. Now, in this connection, may I know whether the Central teams would be sent immediately to see the ground realities and make their assessment so that the Central Government may not accuse the State Governments saying that they have inflaed their demands.

Lastly, about the crisis management group. This is the first time that I have heard of such a thing. What is the crisis?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): He will explain.

SHRI CHITTA BASU: What is the crisis? What is the management? Who constitute this group? What are the functions of this crisis management group? Would the hon. Minister kindly explain because it is for the first time that I have heard of such a group? Are you creating a crisis? Is the group's duty only to create a crisis or solve a crisis?

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : श्री चतुरानन मिश्र ।

डा० बापू कालदाते : महोदय, आपका ध्यान हमारी तरफ नहीं जाता है क्योंकि हम चुप बैठे रहते हैं ।

उपसभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई) : हर पार्टी की तरफ से पहले एक-एक सदस्य बोलेंगे, आपका सेकेन्ड राउन्ड में नम्बर आएगा ।

DR. BAPU KALDATE: I was associated with the special mention. I am waiting for such a long time. You are calling everybody. Because I keep quiet nobody pays attention to me. Shall I shout?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That is not the reason why I have not allowed you.

SHRI DHARAM PAL (Jammu and Kashmir): I am not catching your eye.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): You will catch my eye in the last. Yes, Mr. Chaturanan Mishra.

श्री चतुरानन मिश्र : उपसभाध्यक्ष महोदय, अभी तुफान, बाढ़ और वर्षा से जो भयंकर क्षति हुई है उससे सारा देश चिन्तित है । अत्यन्त ही दुखद बात है कि इस तरह की घटना घटी है । लेकिन हमारे देश में इस बार दक्षिण के लोगों के साथ यह घटना घटी है । कभी उत्तर के साथ, कभी पूर्व के साथ ऐसा होता है । इसलिए हमें लगता है कि बाढ़ और तूफान की विपत्ति के साथ हम लोगों की ऐसी अच्छी दोस्ती है कि ये बराबर साथ रहती हैं । हमारी सरकार इसको हमसे अलग करने में अभी सफल नहीं हुई । असम में बाढ़ आती है, यह कोई नई बात नहीं है । जब से हमारी अक्ल हुई है तब से बराबर हम देख रहे हैं कि असम में बाढ़ आती है । बराबर मंत्री महोदय उठकर कहते हैं कि जो क्षति होगी उसका हम सर्वे करवाएंगे । अभी मुख्य मंत्री ने हवाई जहाज से यात्रा की है, थोड़े दिनों के बाद प्रधान मंत्री हवाई यात्रा करेंगे । पहले प्लड का विजिट होगा, फिर मिनिस्टर विजिट करते हैं और फिर ड्राउट विजिट हो जाता है । फिर आफिसियल टीम विजिट करती है । यह सिलसिला बना हुआ है और यह कोई नई बात नहीं है । नई बात यही है कि इतने सौ आदमी बेमौत के शिकार हुए हैं । आप दूरदर्शन पर कितने दिनों से हल्ला कर रहे थे कि सुपर कम्प्यूटर लाये हैं, अमेरिका से ला रहे हैं । मैं जानना चाहता हूं कि वह सुपर कम्प्यूटर आप लोगों के डेरे में है या कहां है ? यह कहा गया था कि 10 दिन पहले खबर मिल जाएगी कि कहां तूफान आएगा और कहां बाढ़ आएगी और कहां क्या होने वाला है । तो फिर यह कृषि मंत्रालय में बंद है या प्राइम मिनिस्टर के यहां बंद है । हम लोगों को बता दीजिये तो हम लोगों को हल्लागुल्ला करने में आसानी होगी कि कहां पर है ।

श्री पवन कुमार बांसल (पंजाब) : अभी तो बात ही हो रही है ।

श्री चतुरानन मिश्र : नहीं, दिल्ली में इंस्टाल हो गया है । आप अमरीकी फेडलस सुपर 30 के बारे में कह रहे हैं ।

श्री पवन कुमार बांसल : आपको पता ही नहीं है कि इसके लिए कितने रेडियम की जरूरत है । मैं सुपर 301 के बारे में नहीं, सुपर कम्प्यूटर की बात करता हूं ।

श्री चतुरानन मिश्र : आप सरकारी पार्टी में हैं, आप ज्यादा ज्ञान रखते हैं । हमें तो इतनी सूचना नहीं दी जाती है । आपको इतना बता दें कि बाढ़ की फोरकास्टिंग के लिए कम्प्यूटर बहुत पहले से दिल्ली में स्थापित है । जबकि बाढ़ हर साल असम में आती है । अब मैं सुपर कम्प्यूटर की बात कर रहा हूं ।

श्री धर्मपाल : अमेरिका से कम्प्यूटर लेने में आपको कोई एतराज तो नहीं है ?

श्री चतुरानन मिश्र : एतराज नहीं, हम तो पूछ रहे हैं । रखे कहां हैं ? हमारी उम्र चली जाएगी तब दिखायेंगे । चार-पांच सौ वोटर तो आपके चले गये । उन लोगों ने क्या कसूर किया था । आप यू०एस०ए० ब्रिटेन आदि कहीं से भी लाइये, आप तो नया भारत दिखाने जा रहे थे । आप बता तो दीजिये कि सुपर कम्प्यूटर कहां है ।

दूसरी बात यह है कि कुछ ही दिनों की बात है, तूफान आया था, मैं भी आन्ध्र के किनारे के हिस्सों में गया था । वहां पर जबर्दस्त तूफान आया था और हर साल आता है और हर साल आप स्टेटमेंट देते हैं । इसलिए हम जानना चाहते हैं कि क्या कोई इनबिल्ट सिस्टम होगा जो इसको देखे ? क्या हम लोगों की उम्र में यह होगा या हम लोग मर जाएंगे तब होगा ? अगर हम लोगों की जिन्दगी में यह होने वाला है तो बताइये कि राहत का क्या इनबिल्ट सिस्टम बना हैं । आप कहते हैं कि सर्वे करेंगे । हमसे पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे उन्होंने कहा कि पहले तो केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के सर्वे अनुमान के फर्क का झगड़ा होता है फिर पार्टी का झगड़ा होता है और इस बीच लोग मरते रहते हैं । कांग्रेस की भी सरकारें हैं । उनका भी यही हाल है । बिहार के भूतपूर्व मुख्य मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं । इनके वक्त जब हमारे यहां बाढ़ आई थी एक साल तो भीतर ही भीतर संचिका में यह भी आप से लड़ रहे थे । इस प्रश्न पर और आपमें यही फर्क है कि आप संचिका में हम लड़ते हैं और हम बाहर लड़ते हैं । इतने का ही हमारे और आपमें फर्क है । इसलिये हम कहना चाहते हैं कि आप कोई इन-बिल्ट सिस्टम कीजिये जिससे सारे देश में एकता स्थापित हो । यह जो विपत्ति आई है इसको भारत की विपत्ति समझा जाये । इसका केंद्र सरकार और राज्य सरकार में बंटवारा मत कीजिये । इसको कांग्रेस पार्टी और विरोधी पार्टी, विपक्ष और शासक दल में मत बांटिए जैसा कि यहां होने लगा है । इसलिए मेरा अनुरोध होगा... (व्यवधान).. एक ने कहा कि 28 जुलाई इज ब्लेकेस्ट डे आफ हिस्ट्री और दूसरे ने कहा कि दिस इज हिस्टोरिकल डे । बाढ़ और तूफान के मामले में यह हो जाय तो और भी मुसीबत है । मैं यह जानना चाहूंगा कि आप क्या कोई इन-बिल्ट सिस्टम बनाने के लिए जा रहे हैं ? मंत्री महोदय, आप खेती को नये दृष्टिकोण से देख रहे हैं जैसा कि आपने कहा । एक माननीय सदस्य ने कहा कि जिस तत्परता से आप राज चला रहे हैं उसी तत्परता से आप रिलीफ का काम कीजिये । हम आपसे कहेंगे कि जिस तत्परता से आप राज चला रहे हैं उसी तत्परता से आप रिलीफ का काम चलायें लेकिन जिस इनएफिसियेंसी से आप राज चला रहे हैं उस इनएफीसियेंसी में आप रिलीफ का काम मत कीजिये, नहीं तो बहुत से लोग मर जायेंगे । इसलिए यह अनुरोध हमें आपसे करना है ।

मुझे एक बात और कहनी है । कंपनसेशन के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्राविजन बना दिया कि अगर कोई मर

क्या तो उसका 10 हजार रुपया दिया जायेगा । अगर ऐसा है तो आप ही लोग मरने के लिए तैयार हो जाय हम लोग 20-20 हजार रुपये दे देंगे ।

श्री भजन लाल : आपको हम नहीं मरने देंगे ।

श्री चतुरानन मिश्र : अभी जो सैंकड़ों मरे हैं वह क्या आपकी इजाजत से मरे हैं ? अगर आप हमारे मरने पर 10 हजार रुपए देते हैं तो आप लोग मरिये हम 20 हजार रुपया देंगे । ...(व्यवधान)... मजाक तो आप उड़ा रहे हैं । मरने वाले व्यक्ति को 10 हजार रुपया क्या यह मजाक नहीं है । ...(व्यवधान)... हवाई जहाज में अगर कोई मर जाता है तो एक लाख देते हैं ...(व्यवधान)...

SHRI V. NARAYANASAMY (Pondicherry): This is being given out of the Prime Minister's Relief Fund. It is not the entire relief amount.

SHRI CHATURANAN MISHRA: I am asking your Government. Prime Minister's Relief Fund is a separate thing.

SHRI V. NARAYANASAMY: Why are you asking the Government? You ask the Kerala Government.

SHRI CHATURANAN MISHRA: You always say that it should be the Kerala Government or it should be the Bengal Government. That is the way you take it. (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Let us not bring politics into it.

श्री चतुरानन मिश्र : हमारी क्लियर बात यह है कि गवर्नमेंट इसको रोकने में फेल कर गई है । इसलिये जो भी सिटीजन मरते हैं, उनमें जो हवाई जहाज के एक्सीडेंट में मरते हैं उनको यह सरकार एक लाख रुपया देती है । इसलिये मैं चाहता हूं कि आप इनको भी इसी दर से हर्जाना दीजिये । आप यह क्यों नहीं कीजियेगा । वे भी इसी देश के सिटीजन हैं । यह क्या कि जो गरीब हैं उनको 5 हजार, 10 हजार रुपया दे दो । इसलिये इस तरह का प्राविजन होना चाहिये ताकि उनको फुल कंपनसेशन मिल सके और उनका रिहैबिलिटेशन हो सके ...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That is his suggestion. Government may accept it or not.

श्री चतुरानन मिश्र : एक बात और है । मैं जानना चाहता हूं कि जहां-जहां फ्लड आया है, मंत्री महोदय के पास जितनी सूचना थी उन्होंने दी । इससे हमको कोई शिकायत नहीं है क्योंकि सारी सूचना तुरन्त नहीं पहुंच सकती । एक माननीय सदस्य ने कहा कि हवाई जहाज से मंत्री महोदय नहीं जा सके इन एरियाज में । वे कार से जाते हैं । हम तो नहीं गये, फ्लड में चलने वाली कार हमारे पास नहीं है । थे यह जानना चाहता हूं कि इस एरिया में कितने लोग क्राप्स इंश्योरेंस के द्वारा कवर्ड हैं और जो लोग एफेक्टेड हैं कितने लोगों को क्राप्स इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलेगा और कितनों को नहीं मिलेगा । ...(व्यवधान) कुछ पता नहीं कि किन-किन को मिले । क्या होगा कि जो पैसे वाले हैं उनको मिल जायेगा और बाकी लोग को नहीं मिलेगा । तब आप सप्लीमेंटरी पूछिएगा दूसरे दिन आप भी चूकियेगा नहीं । इसलिए अन्तिम बात में यह कहना चाहूंगा कि यह चूंकि राष्ट्रीय विपत्ति है इसलिए सारे देश को रिलीफ वर्क के लिए एक राष्ट्रीय आह्वान होना चाहिये । राष्ट्रपति आह्वान करें । हम चाहेंगे जितने भी हमारे औद्योगिक मजदूर हैं वह एक दिन की तनख्वाह इस रिलीफ फण्ड में दें । राष्ट्रपति इसका आह्वान करें । कोई रास्ता आप निकालिये । हम को प्रधानमंत्री फंड के नाम से कोई एलर्जी नहीं है । हम तो यह चाहते हैं कि काम होना चाहिये । हम यह चाहेंगे कि राष्ट्रपति इसलिए दें क्योंकि यह नान-कंट्रोवर्शियल है । इसी तरह से आप इंडस्ट्री को भी कहें कि इंडस्ट्रीज भी योगदान दें ताकि तुरंत उनको राहत पहुंच सके । इसलिए मेरा यह प्रश्न होगा कि

[श्री चतरानन मिश्र]

सरकार इसके बारे में क्या सोचती है । एक बार बिहार में यह कहूंगा कि इस विपत्ति को राष्ट्रीय विपत्ति समझ कर तमाम लोगों को इसका मुकाबला करना चाहिये न कि पार्टिजन वेसे जैसे शासक पार्टी के लोग चाहें ।

श्री राम चन्द्र विकल : उपसभाध्यक्ष महोदय, यह दैवी आपदा आज देश के काफी बड़े हिस्से में विशेषकर महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश और गुजरात में आई है । देश के बहुत बड़े भूभाग पर यह दैवी आपदा करीब चार पांच रोज से आई हुई है । कल मने स्पेशल मेंशन इस पर दिया था । मैं भी चेअर से यह अपील करना चाहूंगा कि इस राष्ट्रीय समस्या को प्रान्तीय और क्षेत्रवाद और पार्टीवाद में न बांटा जाए । कृषि मंत्री जी ने वक्तव्य दिया है मैं उनको इस बात के लिए बधाई देता हूं । उन्होंने सोमवार को इस पर विवाद का भी आश्वासन दिया है इसके लिए मैं उनको पेशगी बधाई देता हूं । मैं उनसे एक बात जानना चाहता हूं कि समाचार पत्रों में जो छपा है लेकिन जो रेडियो में खबरें आ रही हैं और जो माननीय मंत्री जी का वक्तव्य है उसमें दिये गये आंकड़ों में फर्क है । रेडियो पर तो आपका नियन्त्रण है फिर यह फर्क क्यों है (व्यवधान)

उप सभाध्यक्ष (श्री जगेश देसाई): मगर नरेश पुगलिया जी ने जो फिगर्ज दी है उन्होंने एक हजार से ज्यादा बताया है । (व्यवधान)

श्री राम चन्द्र विकल: सरकार को यह बात जाननी चाहिये । उसकी एजेंसी कुछ तेज होनी चाहिये । समाचार पत्रों से । रेडियो तो गवर्नमेंट का है । दूसरा यह है कि आज के वैज्ञानिक युग में कुछ जल्दी जानकारी भी होनी चाहिये । जो दैवी आपदाएं आती हैं इनका पहले से ही आभास हो जाना चाहिये । यह दैवी आपदा है मैं इसमें सरकार का दोष नहीं बता रहा हूं लेकिन समुद्री तूफान, बाढ़, अतिवृष्टि और भूमि का खिसकना चार-पांच तरह की दुखद घटनाएं देशव्यापी हुई है हम मृतकों के परिवारों को अपनी तरफ से और सदन की तरफ से संवेदना व्यक्त करना चाहते हैं । मैं महाराष्ट्र विधानसभा का धन्यवाद करता हूं उन्होंने इस तरह का प्रस्ताव पास कर के बिना किसी कार्यवाही के अपना कार्य स्थगित कर दिया इसलिए महाराष्ट्र सरकार और विधानसभा भी बधाई के पात्र है । यह किसी प्रान्त, पार्टी या भाषा का सवाल नहीं है । मृतकों के परिवारों को जल्दी से जल्दी सहायता केन्द्रीय सरकार दे राज्य सरकार दें प्राइम मिनिस्टर फण्ड से या चीफ मिनिस्टर रिलीफ फण्ड से जाए और जनता से अपील कर के भी हम को सहायता जरूर पहुचानी चाहिये । यह उनके साथ हमदर्दी का वक्त है । साथ ही साथ पशुओं की भी हानि हुई है उसके भी आंकड़े कृषि मंत्री जी को मंगाने चाहियें या उनको तुरंत सहायता पहुंचाने की आवश्यकता है । इसके अलावा मैं चाहता हूं कि कृषि मंत्री जी बाढ़ और वर्षा के बाद भयावह बीमारियां पशुओं और मनुष्यों में जो फैलती हैं उनको रोकथाम के लिए भी पहले से इन्तजाम होना चाहिये । किसानों और मजदूरों की जो क्षति हुई है, किसान की जो फसल बरबाद हुई है, उसकी जो पशुओं की हानि हुई है, मकान गिर हैं, विभिन्न तरह की दैवी आपदाओं में उसका सर्वनाश हो जाता है इसमें उनकी पूरी मदद होनी चाहिये । साथ ही जो फसल बीमा है उस पर तेजी से वास्तविक रूप से अमल होना चाहिये । मैं एक और कृषि मंत्री जी से निवेदन करूं, खुद कृषि मंत्री जी जानकारी रखते होंगे क्योंकि वे गांव से आते हैं ऐसी दैवी आपदाओं के वक्त में भी सही और समय पर मदद लोगों को नहीं पहुंचती है । इसमें भी लोग कुछ न कुछ गड़बड़ी कर देते हैं । तो यह चेकिंग आप अपने द्वारा भी और राज्य सरकारों के द्वारा भी इसकी जरा जानकारी करवायें, ताकि इस हमदर्दी के मौके पर कोई गड़बड़ी न हो ।

मैं फिर आपके द्वारा कृषि मंत्री जी से चाहूंगा कि चाहे वह तमिलनाडु का इलाका हो, चाहे केरल का हो, चाहे आन्ध्र का हो, चाहे महाराष्ट्र का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, चाहे गुजरात का हो, जहां भी दैवी आपत्ति है, वहां की राज्य सरकारों से तुरंत जानकारी लें, अपनी जानकारी भी लें और उनकी राज्य सरकारें क्या मदद पहुंचा रही हैं, उसकी भी आप जानकारी लें। चारों तरफ से आप अपनी जानकारी लेकर, तुरंत मदद पहुंचायें। उनकी क्षतिपूर्ति होना तो असंभव है, यह मैं मानता हूं, पर यथाशक्ति केंद्र, राज्य सरकारें और समाज जितनी भी मदद कर सकती हैं, वह उनकी होनी चाहिए।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त करता हूं।

डा० बापू कालिदास : उपसभाध्यक्ष जी, यह बात सही है कि यह एक राष्ट्रीय आपत्ति या विपत्ति है और जिसके संदर्भ में सारे सदन के मन में दुख है, उसको ध्यान में रखते हुए जिस ढंग की योजना इसके बारे में करनी चाहिए, वह योजना हमारे दुख का तालमेल खाती नहीं है, ऐसा मुझे बहुत लग रहा है।

जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मुझे याद है कि 15-20 साल पहले पूना में पानशेत बांध टूट गया था। उसके बाद इतनी बड़ी आपत्ति महाराष्ट्र में शायद पहली बार आई होगी। उस समय सारा पूना शहर बह गया था, लेकिन यह एक शहर का मामला नहीं है, सारे महाराष्ट्र के जो भी जिले हैं उनमें चंदेक, दो-तीन जिले छोड़ दें, तो सारे जिले इस अति-वृष्टि से प्रभावित हुए हैं।

जो आंकड़े सरकार ने आपके पास भेजे और यह अच्छी बात रही है कि महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत हमें, जो यहां के संसद सदस्य हैं, उन सब के पास जो ताजी से ताजी उनके हाथ में इनफार्मेशन थी, वह उन्होंने हमारे हाथ में दे दी।

मेरी दो-तीन बातें हैं। मैं खुश होता, अगर आप अपने बयान में बता देते कि 24 तारीख का मसला आते ही इन पांच राज्यों में या दस राज्यों में आपकी टीम्स जा पहुंची है और जो कुछ भी जायजा है इस आपत्ति के संदर्भ में, वह काम शुरू हो चुका है। ऐसा अगर आपके बयान में होता, तो मुझे बहुत खुशी होती, लेकिन यह नहीं है।

दूसरी बात मुझे एक और भी लगती है कि शायद राज्यों ने आपसे तुरंत कुछ मांगा भी होगा। आपने तो कहा है कि 204—25 करोड़ रुपए की जो मार्जिनल मनी है, लेकिन हो सकता है कि राज्यों ने तुरंत भी मांग की होगी आपके पास कि उनको पैसा चाहिए। मैं जानना चाहूंगा कि क्या राज्यों ने तुरंत कुछ मांग की है, क्या? अगर कुछ की है, तो उसके रेस्पांस में आपने उनके लिए क्या मंजूर किया है?

मैं तो यह कहना चाहूंगा कि 204 करोड़ रुपये का यह मार्जिनल मनी इतना कम है—मैं तो अभी यह गुजारिश करूंगा कि आप उठ कर इस सदन में आज कहें कि 204 करोड़ का, जिस ढंग का यह माहौल है, जिस ढंग का नुकसान हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए कहिए—आप इसको तुरंत दुगना करके कहिए, आप ऐलान करिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूं आपसे कि आप इस क्षति को देखते हुए, इस वास्तविकता को देखते हुए—आप यह ऐलान करते हैं कि "यह मार्जिनल मनी पांच सौ करोड़ की आज मैं कर देता हूं। अगर आप ऐसा करेंगे, तो इससे लोगों में ज्यादा विश्वास आएगा, बजाए इसके कि हम कहें कि महाराष्ट्र के लिए पचास दें, कोई कहे कि तमिल नाडु के लिए पचास दें या और कोई राज्य बात करके—अगर यह राष्ट्रीय आपत्ति है, तो राष्ट्र के नाम से कुछ काम होने की आवश्यकता है और मैं आपसे जरूर प्रार्थना करूंगा कि आप हमारे जो प्रश्न है, उसके उत्तर में इस बात को जरूर कहेंगे कि आज हम पांच सौ करोड़ देश को देने के लिए तैयार रखे हुए हैं और जो कुछ ज्यादा लगे, चाहे उसको देने की तैयारी हम रख चुके हैं, यह अगरक कहेंगे,

[डा० बापू कालदाते]

तो राज्य की सरकार को भी एक नया विश्वास इससे प्राप्त होगा । इसके बारे में भी आप हमको कुछ कहेंगे ।

तीसरी बात मैं बिलकुल स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि भले ही आप कितना भी कृषि के बारे में कहते रहिए, सरकार कृषि की तरफ उपेक्षा की दृष्टि से देखती है । यह सिलसिला आज तक जारी रहा है ।

अब देखिये कि महाराष्ट्र का सारा नुकसान आप गिनिये, जो हमारे पास सरकार की तरफ से या जो कुछ भी अनआफिशयल इनफर्मेशन आई है, उसके मुताबिक हम कहते हैं कि महाराष्ट्र में मनुष्यों की मृत्यु की संख्या, जानवरों की मृत्यु की संख्या, फसलों का हुआ नुकसान, मकानों की हुई बर्बादी, यह सारा अगर आप देखेंगे, तो दस करोड़ तक की बात चल रही है । यह आप इतना तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन इसको इतना मार्जिनल मत कराइए जिससे कि गरीब लोगों के मन में ऐसा आ जाय कि बड़ी आपत्तियों में भी हमारी तरफ गरीबों की दृष्टि से देखा जाता है । इसमें गरीब या कृषि के लोगों की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए और खासकर के कृषि के लोगों को ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका इस ओर ध्यान दिलाता हूं कि अभी हाल में महाराष्ट्र में ड्राउट हो गया और सरकार ने फैसला किया कि ड्राउट के कारण जो लोन वापस नहीं कर सकते हैं, उनके लिए बंटधारा करके उसे दस हिस्सों में बना दिया और सरकार ने कहा कि यह गरीब लोग हैं, इनको 10 परसेंट के बजाय 6 परसेंट पर लोन देते हैं तो बीच में आपका नवार्ड आ गया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि यह राष्ट्रीय पालिसी है । यानी यहां पर जो किसानों को हम कोई सहूलियतें देने का प्रयास करते हैं तो बीच में कभी फाइनेंस मिनिस्ट्री आ जाती है तो कभी कोई मिनिस्ट्री आ जाती है, जिससे जो कुछ उन्हें देना होता है, उसमें रुकावटें आ जाती हैं ।.... (व्यवधान) ....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): That also at the expense of the State Government.

DR. BAPU KALDATE: That is what I am saying.

अब राज्य सरकार तैयार है, आप तैयार नहीं हैं, ऐसा मत करिए । यह किसानों की तरफ देखने का आपका रवैया बदलना चाहिए । आपकी जैसी बहुत सराहना बहुत मित्रों ने की है, हम भी जानते हैं कि आप कृषि से संलग्न व्यक्ति हैं और इसलिए हम यह चाहते हैं कि कम से कम आपके जरिए कोई एक नया माहोल खडा हो, जिससे कृषि की तरफ जितनी अपेक्षा है, उससे हटकर मदद करने की दृष्टि से देखा जा रहा है, ऐसा कुछ काम आपको करना होगा । इसमें रुकावट लाने का काम नहीं होना चाहिए ।

उपसभाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सब लोगों ने कहा है, मैं भी चतुरानन जी से सहमत हूं कि यह एक अजीब चीज इस देश में चलती है कि अगर किसान मर गया हो दस हजार और हवाई जहाज से मर गया तो एक लाख के धनी हो जाते हैं । यह जो फर्क करने की बात इस देश में चलती है, इससे बड़ा रंज होता है, । मैं कहूंगा कि कोई भी इंसान मरे, अगर दस हजार है, तो दस हजार सबको करिए । हवाई जहाज से सफर करने वाले लोगों का आपके एक लाख से कुछ होने वाला नहीं है, उनके पास कई लाख रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन अगर छोटा किसान मर जाएगा और उसके परिवार को अगर आप बीस हजार दे देंगे तो उसका परिवार शायद कुछ दिन के लिए चल सकता है । इतना फर्क किसानों के बारे में जो आज तक चला है, कम से कम उसको तो कम करिए । अगर आप यह नहीं कर सकते तो यह कर दीजिए कि इसका भी एक लाख । इसमें कोई

कम ज्यादा करने की बात नहीं है । बल्कि इंसानियत का सवाल है । गरीबों को यह महसूस होने दीजिए कि मृत्यु के समय, जिन्दगी में तो शायद हम एक स्तर पर उनको नहीं ला पाए, कम से कम मृत्यु के समय एक इंसान का दूसरे इंसान से फर्क नहीं करते हैं । तो इंसानियत की दृष्टि से इसको देखा जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं ।

अंत में मैं यह भी कहूंगा कि यह बात सही कही गई । महाराष्ट्र की हद तक मैं यह बात कह सकता हूं कि महाराष्ट्र में यह धनराशि इकट्ठा करने का काम शुरू हुआ होगा । मैं यह मानता हूं कि सरकार की जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है लेकिन आपत्ति के समय जनता की भी कुछ जिम्मेदारी कम नहीं है । हमने देखा है पानसेत के समय सारा महाराष्ट्र उठ खडा हुआ था और जनता की जो स्वयं सेवी संस्थायें हैं वे भी उठ खड़ी हुई थीं और मदद का कार्यक्रम बडा जोरदार चलता रहा । मैं मानता हूं कि यह कार्यक्रम महाराष्ट्र में शुरु भी हुआ होगा. लेकिन जैसा चतुरानन जी का सुझाव है, मुझे बहुत पसंद है कि राष्ट्रीय विपत्ति के समय सारा राष्ट्र अपना हिस्सा बांटें सिर्फ सरकार की नीति पर निर्भर न रहें । जितना हम योगदान करते रहेंगे, जनता योगदान करती रहेगी, उतना ही लोकतंत्र सुदृढ हो सकता है । इस दृष्टि से अगर राष्ट्रपति के माध्यम से हम इस विपत्ति के लिए एक कोष बनाने की बात सोचें तो इस पर जरूर सोच-विचार करना चाहिए जिसमें हम लोग जो यहां सदस्य हैं या नहीं सारे देश की जनता इसमें अपना योगदान कर सकें । । इससे जो लोग विपत्ति में फंसे हुए हैं, उनको भी एक नया आश्वासन मिलेगा यह सरकार और जनता की तरफ से उनको आश्वासन करने का समय है मैं समझता हूं कि सरकार खडी रहेगी, जनता भी खडी रहेगी और तात्कालिक आपत्ति में, मैं इसमें जो बुनियादी सवाल है, फ्लडस वगैरहा में नहीं जा रहा, लेकिन जो तात्कालिक आज की बात है, आपत्ति है, उस पर कहता हूं, इस आज की आपत्ति में एक नया माहोल पैदा करने का प्रयास हम सब की तरफ से होगा, ऐसा मैं मानता हूं तो इसमें जो भी सुझाव हमने दिए हैं, उन पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहता हूं, धन्यवाद ।

श्री राम प्रवेश सिंह : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, यह जो माननीय कृषि मंत्री जी ने बयान पढ़ा इसे ब्यूरेक्रेटस के लोगों ने तैयार किया है । इसमें दो तीन बातें साफ होती है और दो-तीन सवाल खडे होते हैं । एक पहला सवाल है, जो कि पैराग्राफ "3" के अंदर से निकलता है, मैं इसको पढता हूं । "लेकिन पिछले कुछ दिनों में देश के अधिकतर भागों में वर्षा में निश्चित वृद्धि हुई है । बंगाल की खाडी के उत्तर-पश्चिम भाग में कम दबाव का एक निश्चित क्षेत्र बना हुआ था जो 22 जुलाई को शाम तक अधिक दबाव वाला क्षेत्र बन चुका था और 23 जुलाई को सुबह तक कलिंगापत्तनम में आन्ध्र प्रदेश के उत्तर भाग को पार कर चुका था ।" इस बात से एक बात स्पष्ट नहीं होती है जो मैं जानना चाहता हूं कि यह कब मालूम हुआ और कब से कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था ? कम दबाव का क्षेत्र बनने से क्या पहले यह खतरा मालूम हुआ कि आज कम दबाव का क्षेत्र बना है तो भारी दबाव के क्षेत्र में यह कितने समय में परिवर्तित हो सकता है, मौसम विज्ञान को यह मालूम हुआ या नहीं ? मौसम विज्ञान ने जब जानकारी हासिल कर ली तो यह प्रभावित होने वाले संभावित क्षेत्रों के लोगों को आगाह किया गया या नहीं कि इस तरह के खतरे बढ़ सकते हैं, बाढ़ आ सकती है, भारी वर्षा हो सकती है ? यह जब मालूम हुआ तो कब मालूम हुआ ? मालूम हुआ तो उस बीच में सूचना जनता को दी गई या नहीं दी गई ?

दूसरी बात है, यह मौसम विज्ञान का दूसरा पैरा है, जिसमें कहा गया है कि

[श्री राम अवधेश सिंह]

"इस साल 1989 के दौरान वर्षा सामान्य के मुकाबले एक से दो प्रतिशत होगी चार प्रतिशत कम या ज्यादा होगी।" पहले से ही मौसम विज्ञान कह रहा है और जब कह रहा है तो उसकी तैयारी सरकार की है या नहीं ?

नम्बर तीन, मैं यह जानना चाहता हूं कि यह 204.25 करोड़ रुपए की जो मार्जन मनी है उसके बारे में पूछना चाहता हूं। मान्यवर, पिछले साल बाढ़ आई थी ऐसी जगह में जहां बाढ़ नहीं आती थी, सितम्बर, 1988 में पंजाब और हरियाणा में बाढ़ आई, जिसमें हरियाणा के दो जिले प्रभावित हुए और पंजाब के तीन जिले प्रभावित हुए। उसके लिए पंजाब को 100 करोड़ रुपया दिया गया और हरियाणा को 42 करोड़ रुपया दिया गया, लेकिन बिहार के 17 जिले प्रभावित हुए तो उसको सिर्फ 14 करोड़ रुपया दिया गया। तो आपातकालीन अवस्था में भी जो प्राकृतिक विपदा आती है उसमें भी राज्य के ऊपर अलग-अलग विभेदकारी दृष्टिकोण से बंटवारा होता है। जो सहायता राशि दी जाती है उसमें भी भेदभाव किया जाता है। 14 करोड़ बिहार को जहां 17 जिले प्रभावित हुए तब दिए गए और हरियाणा के दो जिले प्रभावित होने पर 42 करोड़ रुपए दिए गए तथा पंजाब के तीन जिले प्रभावित होने पर 102 करोड़ रुपए दिए गए। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश, असम के जो पूर्वी राज्य हैं उनमें अगर विपदा आती है तो उसके साथ हर तरह से भेदभाव किया जाता है इस विपदा में सहायता राशि में भी क्या भेदभाव किया जाएगा ? इसी से संबंधित, मैं एक और सवाल पूछना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि देश में कुछ इलाके फ्लड प्रोन हैं, जो असंभावी रूप से वहां बाढ़ आती है उसमें उत्तर बिहार बिना बात के हर साल बाढ़ का शिकार होता है। जहां बाढ़ नहीं आती है वहां बाढ़ आ गई और जहां आती हैं, वहां अभी बाढ़ आना बाकी है लेकिन जहां निश्चित आने ही वाली है, जबकि मौसम विज्ञान खुद कहता है एक से दो प्रतिशत वर्षा इस साल होगी तो क्या माननीय मंत्री जी बताने की कोशिश करेंगे कि उत्तर बिहार जो हमेशा बाढ़ की चपेट में रहता है उसके लिए पहले से कुछ तैयारी है ? जब सदन नहीं रहेगा 11 अगस्त के बाद और बाढ़ आयेगी बिहार में, कोई चर्चा करने वाली चीज यहां दिल्ली में नहीं रह जाएगी तो उसकी कुछ तैयारी पहले से है या नहीं ? नहीं तो फिर ये लोग कहेंगे कि अब तो हमको जानकारी नहीं है। इसलिए बिहार की बाढ़-प्रोन स्थिति को देखते हुए क्या बिहार के लिए सरकार पहले से इंतजाम करने के बारे में सोच रही है ?

क्योंकि वहां बाढ़ आना निश्चित है। जब एवरेज से कम वर्षा भी होती है तब भी उत्तर बिहार के 17-18 जिले बाढ़ में डूबे रहते हैं। तो बिहार को बाढ़ से बचाने के लिए क्या कुछ इंतजाम है और उसी तरह के विभेदकारी इंतजाम भी नहीं होने चाहिए कि 17 जिलों में 14 करोड़ और हरियाणा में 2 जिलों में 42 करोड़। यदि ऐसा ही रहेगा तो यह सही नहीं होगा। मैं यह भी कहूंगा कि आपने 10 हजार की जो राशि बतायी है वह बिल्कुल अमानवीय है। आज जहाज से मरने वाले को एक लाख देते हैं। कोई यह तो नहीं चाहेगा कि हम बाढ़ में डूबकर मर जाए। जब कोई गरीब आदमी मरेगा तो उसके परिवार के भरण-पोषण के लिए भी एक लाख की राशि दी जानी चाहिए। यही मेरा कहना है। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी यह स्पष्ट बतायें कि विभेदकारी ढंग से राशि का आवंटन नहीं होगा जैसे कि 1988 में हुआ था।

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar): Mr. Vice-Chairman, this calamity is familiar except that this year also it has come and we have to take note of that — it has affected also some new regions, apart from the familiar regions. Let me commend the Minister for coming to the House earliest with the statement although he has promised that he is going to come back with subsequent

additions. (*Interruptions*) I would also like to go on record that the Prime Minister has responded with tremendous promptness in releasing resources from the Prime Minister's Relief Fund for the benefit of the victims of this flood. The clarifications that I am seeking from the honourable Minister relate to several areas. One: the weather forecast that stated that the monsoon would be to the extent of 102% has actually turned out to be 106%. One point is very clear. We were expecting a more than normal monsoon except that it has become much more than normal. Was our preparatory step adequate keeping in view this advance warning from the weather forecast? The second area is when it comes to the estimate of damages, the Central team, or, for that matter, a combination of Central and State teams, have proved to be inadequate. I am particularly drawing the attention of the House to what happened in the case of Bihar during the last flood. There is a lot of controversy. In any event, it was only when the dust settled down that it turned out that the former estimates were far inadequate of the real magnitude of the damage. And I am quite sure, as a result, the degree of compensation, the amount of compensation, must have been inadequate. Is there some guarantee that this time the composition and the competence of the damage estimating team, whether of the Central Government or of the State Government or a combination of them is likely to be better more effective and more accurate so that people do not suffer as a result of poor and wrong estimate? Third: A reference has been made to margin money. We know the ways and means position of State Governments. For the Central Government to pin its hopes that the margin money resources will be used on a priority basis for the benefit of the victims is somewhat naive if not true and optimistic. I would submit that rather than waiting for a sequential first use of the margin money for the benefit of relief, the Central Government should release sufficient supplementary funds assuming that even if in the books of account the margin money is there, it is not readily available for liquidity purposes. Only then will we find that succour will come to those who are in need. Fourth: Whenever the question of compensation comes, invariably the need of the individual, compensation to the individual, is considered and compensation is given. Of course, it is as it should be. But when it comes to compensating a State for the damage to its infrastructure, I am not sure if the Central Government takes into consideration this aspect. Now, I am particularly trying to draw the attention of the Minister to the fact that the inadequacy of or the damage to the infrastructure turns out to be more penal. Take, for example, this thing: The medical relief team could not reach the villages of North Bihar earlier because the roads had been washed away in the previous floods. Why were the roads washed away? It is because, in the first place they are poorly constructed and, secondly, in the precious floods, the repairs have not been adequate. Is there some evidence that the Government is rationalising the pattern of compensation for the purpose of strengthening the infrastructure within the total flood relief programme that we have?

The other thing that comes to my mind is that so far as the Government machinery's responsiveness to the management of drought relief is concerned, it has been proved beyond any shadow of doubt that it has been effective, that it has received appreciation not only of the nation, but also of the other countries and other agencies like the World Bank. Is there some evidence to show that the responsiveness and resilience of the Central and State administrations would be equally effective going by the historical track record and that it does not turn out to be otherwise? Is there anything better and

[Prof. Chandresh P. Thakur].

anything new done and if there is some thing that is being done, what are those concrete steps which bring credibility to the system of administration with regard to the management of flood relief?

Finally, Sir, I would like to submit that we have heard a derisive reference made to crisis management. But there is something called disaster management. Disaster is frequent in this country and no region of the country has escaped the consequences of a disaster. There is a body of literature, techniques, facilities, etc. for disaster management. Has the Ministry of Agriculture along with its counterparts in the States been exposed, particularly the critical component of the administration, to the techniques of disaster management and is there some evidence that some learning has been picked up and is going to be used when we run around the country for the management of disaster?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Now, there are three or four Members who want to speak and whose requests have come later. I will allow these two Members first and other Members. I will allow only three or four minutes. Yes, Mr. Hanumantha Rao.

SHRI S. S. AHLUWALIA (Bihar): I have been waiting for my turn... (*Interruptions*)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): I cannot help, you see.

SHRI S. S. AHLUWALIA: We also have got our rights... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Whatever rights are there will always be honoured... (*Interruptions*)...

SHRI DHARAM PAL: Sir, you are the custodian of our rights... (*Interruptions*)...

SHRI S. S. AHLUWALIA: Everytime we have to stand with a begging bowl... (*Interruptions*)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): All right. I will try to give chances to as many Members as possible. Yes, Mr. Rao.

SHRI MOTURU HANUMANTHA RAO: Sir, it is very unfortunate that this year the calamity of floods has caused extensive damage in so many States. Maharashtra being the worst with Andhra Pradesh perhaps coming next. Five hundred and eighty-six lives have been lost and properties have been damaged. The point here is that whenever such calamities take place, we all express our sentiments and we plead for some relief measures on a war-footing. But that relief on war-footing will come only in words and nothing happens in practice. On this very same floor, Sir, I was expressing my apprehension last year with regard to the Godavari floods and I had said that the teams would be sent very late and their assessment would be given very much later and the help also rendered finally would be very little. The same thing should not happen this year also. War-footing means it should really be so. But the concluding part of the statement of the Minister does not indicate that they are moving very fast or in a rapid way for providing relief. The team is there. There is no use of the team going there to assess the loss after two months or one and a half months. Last year it happened after we complained here that the team came there one month afterwards and their assessment was given one month later or two months later. Finally, the assistance given was very meagre, and not up to the mark. So like this it should not happen again. The point is that when we take it up on war-footing immediately our teams must also go round and see. What do they see after two months? For instance, because of the Godavari floods all the plantation

is washed off. The people of course cannot keep quiet. They beg, borrow or steal or do something. Stealing of course they do not do. They incur very great loss and also borrow money from somewhere and again plant. So if after two months your teams go there, the plantation is all right, the fields are all right and plants are growing. If this is the way a report is done what assessment could be made? So my point is that they should immediately go. As justice delayed is justice denied relief delayed is relief denied. So that happens because the funds would be diverted, so much of corruption would creep in, and directly it does not reach the masses at all, the suffering people. So like that it happens. All these things should be taken into consideration and immediate relief measures are to be attended to by the Central Government. It is not enough to say that State Governments are already doing this. State Governments might be doing their bit but at the same time the Centre is to give so much of help. As many of my hon. colleagues have expressed, Rs. 204 crores of margin money is very meagre compared to the loss we have been witnessing throughout the country. So what is the use of saying that Rs. 204 crores of margin money is there with States. How much is it? And I have seen in the Press that Rs. 40 lakhs has been donated from the Prime Minister's Relief Fund. What does it amount to? So all these measures do not meet the needs of the situation. They should rush with relief. Tentative relief must be immediately given. We know what is happening in so many States. Immediate steps should be taken from the Centre instead of waiting for the State Governments to send their reports and then take time to send the teams for assessment. It does not amount to any help in the hour of need. So please see that immediately the teams are sent and they take their own assessments. On the basis of that, even temporary relief to the extent it is assessed be given to the States so that they can also move into action and render immediate relief to the suffering people.

Every year we are facing this calamity and naturally some permanent measures are to be taken. Lining of *bunds* is one of the control measures that has to be attended to. It has been talked of again and again but nothing happens. Permanent control measures are not attended to at all. That is exactly why so much suffering also is recurring.

The second thing is that at this hour of suffering, people need very much the food supply. Rice must be supplied immediately. If rice is not supplied in abundance, that means after ten days, 20 days or 30 days similar suffering would go on. Somehow they live. Some people make a living and some people die also. So, immediate help must be rendered and the States must be provided with abundant stocks of rice in order to see that every suffering family is immediately given some rice. With these words, I conclude. Thank you.

श्री राम नरेश यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय, यह जो राष्ट्रीय प्राकृतिक विपदा है यह प्राकृतिक विपदा कई राज्यों में, करीब 9 राज्यों में पूरी तरह से आई है । 9 राज्य इस से प्रभावित हुए हैं जिसके संबंध में माननीय कृषि मंत्री जी ने जो कुछ सूचना उपलब्ध थी उसके जरिए सदन को अवगत कराया । कैसे बात स्पष्ट है कि सरकार ने बहुत तत्परता के साथ कार्रवाई करना आरम्भ कर दिया है । सबसे पहले खेत में होने वाली क्षति के लिए 204 करोड़ रुपए मार्जिन मनी देने का काम किया है और 10 हजार रुपए . . .

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : मार्जिन मनी नहीं . . . **(व्यवधान)**

श्री राम नरेश यादव : इसके साथ-साथ 10 हजार रुपए मृतक व्यक्तियों के परिवारों को सहायता के रूप में प्रधान मंत्री कोष से देने की बात की गयी है । इसके लिए प्रधान मंत्री जी बधाई और धन्यवाद के पात्र हैं । मैं निवेदन कर

[श्री राम नरेश यादव]

चाहता हूं कि जिस तरह से किसानों के खेतों को क्षति हुई है और लोग मरे हैं, उसके बारे में जो आंकड़े आये हैं अखबारों में वह 750 लोग मारे जाने के आये हैं और मंत्री जी ने जो आंकड़े दिए हैं कुल मिलाकर 586 हैं —थोड़ा इधर-उधर हो सकता है। मंत्री जी फिर जानकारी करने के बाद सोमवार को सदन के सामने रखेंगे। इस संबंध में अवश्य सही तस्वीर हमारे सामने, सदन के सामने आनी चाहिए।

एक बात यह कही गयी है कि राज्य सरकारों को जितनी सहायता की जरूरत होगी हम उनको उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे। मेरा कहना यह है कि राज्य सरकार किस तरह से कब मांगती है इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, न उसकी प्रतीक्षा करनी चाहिए। बल्कि आपको इस आपदा में, ऐसे कष्ट के समय में अधिक से अधिक इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कहीं भी किसी भी तरह से उनको पैसे की कमी न हो। वैसे राज्य सरकारें अपने स्तर से प्रयास कर ही रही हैं। हम जानते हैं कि राज्य सरकारों के पास कितने सीमित साधन हैं और उन सीमित साधनों के आधार पर इस प्राकृतिक विपदा का सामना नहीं कर सकते किसी भी तरह से। एक तो इस आधार पर कृषि मंत्री जी को अपना वक्तव्य देना चाहिए कि किसी भी तरह से पैसे की कमी इस राष्ट्रीय आपदा के समय में बाधा नहीं पड़ने देंगे। मैं चाहूंगा मंत्री जी इस बारे में सदन को विश्वास दिलायेंगे।

दूसरी बात 10 हजार की जो धनराशि रखी गयी है यह बहुत कम है। मान्यवर, किसान लोग, गांव के लोग, घरों के लोग जिन परिस्थितियों में रहते हैं, क्या परिस्थिति उनकी बनती है इसको देखते हुए दस हजार रुपए आपने दिए हैं, पहली किश्त के रूप में दिए गए हैं प्रधान मंत्री कोष से तो ठीक है और राज्य सरकार भी कुछ देगी लेकिन यह धनराशि अपर्याप्त है। इसको बढ़ाने के लिए कृषि मंत्री को ध्यान देना चाहिए। जो लोग चले गए हैं वे लौटने वाले नहीं हैं लेकिन उसके परिवार में जो लोग बचे हैं उनको इस बात का अहसास हो जाए कि इस राष्ट्रीय विपदा के अवसर पर सरकार ने हमारी कुछ मदद की है। साथ ही एक बात और इस में खड़ी हो जाती है लोगों को निकालने की और उनके पुनर्वास करने की। इसमें आपको अच्छे स्तर पर काम करना चाहिए। यह भी देखना चाहिए कि किसी भी तरह से उन लोगों को खाद्यान्न की कमी न हो, मिट्टी के तेल की कमी न हो, किसी भी तरह से उनको इस बात का अहसास न हो कि इस राष्ट्रीय विपदा में फंस गए हैं तो कोई उनको पूछने वाला नहीं है। यह अहसास उनको नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ स्थान-स्थान पर जो नदियां हैं उनके किनारे बंद पड़े हैं। ऐसा निर्देश देना चाहिए कि राज्य सरकारें अपनी जिम्मेदारी का पालन करें। वहां पर मिलिटरी को तैनात करना चाहिए जिससे कि कहीं पर बांध टूटने न पाए। बांध टूटने से एक भयंकर स्थिति पूरे देश के पैमाने पर पैदा होगी जिसका सामना राज्य सरकारों के लिए संभव नहीं होगा। टीम भेजने की बात आयी है। जहां पर असैस करना है वहां पर टीम भेजने का काम होना चाहिए, वहां पर विलम्ब नहीं होना चाहिए। इसके साथ-साथ एक और स्थिति यह आयेगी, आ भी रही है कि जो लोग बाढ़ से प्रभावित हैं उनको दूसरी जगहों पर रखा जा रहा है। उनको भोजन की कमी, उनके पशुओं के लिए चारे की कमी नहीं होनी चाहिए। इसके लिए पूरी तरह से व्यवस्था होनी चाहिए। सेन्ट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो टीम इस काम के लिए जाए वह दवाओं से पूरी तरह लैस हो ताकि उनको किसी भी चीज की कमी न रहे। उनको इस बात की चिंता न रहे कि दवाएं डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर से कैसे आयेंगी, डाक्टर के पास कैसे जायेंगे। उन जगहों पर सचल अस्पताल उपलब्ध होने चाहिए, दवायें उपलब्ध होनी चाहिए ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। राशन और मिट्टी के तेल की समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। इन बातों की तरफ ध्यान

दिया जाना चाहिए और मैं सरकार से अपील करता हूं कि इस तरफ युद्ध स्तर पर ध्यान दिया जाना चाहिए । यह एक राष्ट्रीय विपदा है । उसका सामना वहां के लोगों और सरकार को करना है । इस संबंध में सदन चिंतित है, सरकार भी चिंतित है और राज्यों के लोग भी चिंतित हैं । सब लोगों की सहानुभूति मृतकों के परिवारों के साथ है ।

SHRI V. NARAYANASAMY: Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you for giving me this opportunity to seek clarifications on a vital subject, that is floods. Sir, the Minister has stated in his statement that during the period June to September, the expected rainfall would be 102 per cent. Sir, from June till the middle of July, it has exceeded beyond 106 per cent, and it is reported that the monsoon is active in the Western Ghats. Sir, Maharashtra is the worst affected State due to floods and cyclone. Sir, here the Minister has stated that as far as Maharashtra is concerned, the loss of life reported so far is 332. And he further stated that a lot of fishermen who are in the sea-shore areas have been missing. Sir, there are newspaper reports to the effect that more than 500 people have died due to cyclone and that more than 2,000 people are missing. Sir, it is reported that 2,000 people are missing from the Konkan and other areas. I would like to know whether those people have been warned earlier by the District administration about the intensity of the cyclone because people would have been very cautious if there had been a warning at least 24 hours earlier about the cyclone. I would like to know whether the forecast was there and people were warned well in advance so that they could safeguard their property and life itself. There is nothing in the report that the people have been given a proper warning in this regard. Sir, even if we go by the figure as per the statement of the hon. Minister, the number of people died is 332 and that is enormous. But I can very well say that the District administration should have been a little cautious and they should have taken precautionary measures so that the life of the people could have been saved.

Sir, another thing is about the relief measures. Sir, I thank the hon. Prime Minister for immediately announcing Rs. 40 lakhs from the Prime Minister's Relief Fund to give Rs. 10,000 each to the families of the persons died. I also thank the hon. Minister for allotting funds to the tune of Rs. 204 crores to various States for looking after the relief works. Sir, the important thing is giving relief by way of supplying food and medicines to the affected people. And the third thing is that persons who have been missing should be located. And the relief work should be taken ub on a war-footing by the State Governments, and the Central Government has to monitor that. Sir, the Crisis Management Group is there to monitor the activities done by the State Governments towards relief. I would like to know from the hon. Minister whether adequate medicines and food materials are there with the States and whether the Central Government is going to provide foodgrains from the Central pool and also medicines to assist the State Governments concerned namely, Maharshtra, Andhra Pradesh, Kerala and other States which have been affected by the floods and what is the total amount which the Central Government is additionally going to spend for that purpose? Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI JAGESH DESAI): Mr. Sreedharan, you have three minutes.

SHRI ARANGIL SREEDHARAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, when I went through the statement made by the hon. Minister, I was shocked by one factor, namely, that the hon. Minister has not expressed any sympathy for the people who have suffered due to

[Shri Arangil Sreedharan]

floods. Sir, many have died, many have lost their homes and many have sought refuge in relief camps. He should have included one sentence in this saying that the Government is sympathetic to those people. In fact, he should have first moved a condolence resolution in this House expressing condolence to those families.

[The Vice-Chairman (Shri V. Narayanasamy) in the Chair]

Sir, it has been rightly pointed out that floods and droughts occur intermittently in this country. Ours is a big country and naturally some big natural calamities are bound to be there at all points of time at one place or the other. We have gone through seven Plans. May I know what are the steps which the Government has taken to meet this situation on a scientific basis? Modern science and modern development can even tame rivers. What exactly is the plan to meet such crisis? Sir, the statement betrays a lack of realism because I do not think that Agriculture Ministry alone can tackle the situation. Roads have been washed away. Rail traffic is disrupted. Houses have collapsed. There has been all round destruction in flood hit areas and I am told that in my own home district several people have become homeless and are refugees and they are being fed in refugee camps and roads have become so bad that it is not possible to travel from one place to another. So there should be a coordination committee of these Ministries, Ministry of Surface Transport Ministry of Food, Ministry of Agriculture and Ministry of Housing. They should have something like a coordination committee of the Congress Party who could coordinate the activities and take a realistic view of the whole situation. I am very sceptical about the study teams. During the last drought a study team from the Centre came to Kerala. One member of the study team asked, where is the drought here? All the coconut trees are green. He has no idea that coconut tree is an evergreen tree. For heaven's sake do not send such people to us who do not know anything about the agricultural resources of a particular State. That has to be gone into and people who are conversant with the agriculture of a State should be sent there in the study teams.

The second thing is what is the time bound-programme for the study teams? They go there, make their own assessment, then there is the State Government's request based on their own information but nobody has laid down any time bound programme for any study teams. Relief is something which cannot be denied beyond a certain period of time. If it is to be effective, it must come immediately, because people are suffering.

Now I come to my State Kerala. Kerala has had her own misfortunes in this calamity. In my State thousands of people are in relief camps. They have to be fed. But what is the reality? The reality is that the ration which was sanctioned to the State, it has been cut down by the Central Government. I do not know why. Every time they say, our stocks are not sufficient. But in newspapers they say, we have a bumper crop. So, when we are facing this calamity, when we are driven to the wall, I would request the hon. Minister to talk to the Food Ministry and give us adequate supply of rice, additional supply of rice, at least for those people who are in the refugee camps. Finally, the amount sanctioned is very meagre. It has already been pointed out here that the amount sanctioned will not even meet the bare necessities of the affected people. We asked for Rs. 47 crores, and then another 22 crores, and all that we got is only Rs. 5 crores. I know Kerala is far away and our agony does not reach Delhi that fast. But people have been talking about the country as a whole. I only request the hon. Minister to make a realistic appraisal of the whole thing and give us more

funds so as to meet this calamitous situation.

श्री मोर्जा इर्शादबेग (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं सिर्फ दो तीन प्वाइंट्स के बारे में क्लेरीफिकेशन चाहूंगा । एक तो मंत्री जी ने बताया है कि अभी पूरी जानकारी सब स्टेट्स से नहीं आई है । अखबारों के जरिये से जानने का मौका मिला है कि गुजरात में कुछ जन-हानि हुई है किन्तु यह स्टेटमेंट में इसके बारे में नहीं कहा गया है । शायद जानकारी नहीं आई होगी । मैं इसके बारे में भी जानना चाहूंगा । दूसरी एक खास बात कहना चाहूंगा जैसे कि विकल जी ने कहा कि जहां इंसानों के मारे जाने की खबर मिली है इसके संबंध में यह कहूंगा कि मवेशियों के बारे में जब उनका पता लगाया जाएगा, राज्य सरकारें उनको आंकड़े देंगी लेकिन इसके बारे में मुझे मंत्री जी से यह पूछना है कि जो पशुधन का नुकसान हुआ है उसके मुआवजे का स्वरूप या सहायता का स्वरूप किस प्रकार का होगा । मैं समझता हूं कि अभी तक ऐसा कोई प्रावधान नहीं है । इसके पहले भी जब यह परिस्थिति हमारे सामने आई थी तब मवेशियों के लिए हमने कुछ मुआवजा केन्द्रीय सरकार से यहां से सहायता की थी, मैं इस संबंध में यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई स्पेसिफिक कानून या नया प्रावधान लाने की बात आप सोचते हैं या इस तरह का कोई आयोजन कर रहे हैं । इस संबंध में किस हद तक इन मवेशियों का जहां पर नुकसान हुआ है उनकी सहायता किस स्वरूप में दी जाएगी इसके बारे में मंत्री जी बताएं । मेरा यह भी कहना है कि जहां-जहां किसानों को नुकसान पहुंचा है या खेती-बाड़ी को नुकसान पहुंचा है वहां पर अगर बीमा लिया गया था तो बीमे का भुगतान फौरन एक महीने के अन्दर इनको कर देना चाहिए । इसके बारे में मंत्री जी विशेष रूप से बताएंगे । तीसरी बात यह है कि जब फ्लड हो जाता है, जब उस जमीन से कुछ दिन के बाद पानी निकल जाता है तो उसका जो उपजाऊपन है वह खत्म हो जाता है । इसलिए पहले यदि उस जमीन के लिए एक प्रतिशत की आवश्यकता थी तो उसकी आवश्यकता दुगुनी, तीन गुनी, दस गुनी हो जाती है अगर उसको फिर से उपजाऊ बनाना है तो मन्त्री जी से मैं यह कहना चाहूंगा कि ऐसी जमीन जो फ्लड से ग्रसित हो गई है, अभी पर्याप्त समय है वर्षा का आगमन हुआ है वर्षा का सीजन चल रहा है, मैं समझता हूं अभी पर्याप्त समय हमारे पास है फिर से किसानों को सही समय पर बीज और खाद हम उपलब्ध करवाएं तो वे फिर से नयी फसल उगाने में सक्षम होंगे । इसलिए अविलम्ब इस बात को देखा जाना चाहिए कि उनको किस ढंग से खाद और बीज जहां पर फसलें क्षतिग्रस्त हो गई हैं किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराए जाएं ताकि फिर से वे अपनी जमीनों में फसल उगा सकें । तीसरी बात यह है कि बैंकों के कर्जों के संबंध में मैं आपसे पूछना चाहूंगा । अगर ऐसे कर्ज जिन्होंने कहीं से लेकर फसल को उगाया था इसके बारे में मंत्री जी क्या करेंगे ! मैं यह मांग करूंगा कि ऐसे जो कर्ज बैंकों के द्वारा या अन्य कोई सरकारी एजेंसियों के द्वारा लिए गए थे उसकी माफी करने के लिए वसूली में क्या रियायत देना चाहेंगे । मैं यह मांग करूंगा कि नयी फसल उगाने के लिए ऐसे किसानों को जिनकी फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं उनको फौरी तौर पर नया ऋण बैंकों और अन्य एजेंसियों से मिल सके । इसके बारे में सरकार क्या सोच रही है और क्या प्रावधान किये हैं इसके बारे में मंत्री जी बताने की कृपा करें । धन्यवाद ।

DR. YELAMANCHILI SIVAJI (Andhra Pradesh): Sir, you are aware that there are fast changes in the geo-climatic conditions throughout the world and more so in our sub-continent. I am not blaming anybody for these changes, I am not blaming anybody for these flash floods and other things. I am not blaming Mr. Rajiv Gandhi or Mr. Bhajan lal. At the same time, I would like to point out that every year, atleast two-thirds or half of the population in the country is affected either by floods or drought or some other natural calamity. But unfortunately, the burden lies on the State

[Dr. Yelamanchili Sivaji]

Governments. So much time is consumed. So much delay takes place. Reports are sought from the State Government and when they are received they are scrutinised here. The all-powerful and all-visible Central teams go to the affected areas after two or three months, make their assessment and give their reports. These reports are considered by the Cabinet or by some Cabinet sub-committee and then it goes to the Ministry of Finance. By the time the relief reaches the States, seven or eight months would have gone by and, therefore, precious little time would be left — three or four months — to spend the entire amount. The money reaches the States by the end of January or at the beginning of February and the State Governments go round the various departments of the Central Government pleading for extension of time up to the the 30th June so that they can spend the amount.

Naturally, the State Governments, whether they are ruled by the Congress (I) or by other parties, would give proposals for huge amounts. They would claim that the loss was very huge because then only they would get at least ten or fifteen per cent of the amount demanded from the Central Government. Naturally, they would claim a very high amount. The Central Government takes seven for eight months for sanctioning even this ten or fifteen per cent of the States' demand. Ultimately, the States are not able to spend even this amount. Curiously, the Congress (I) people in the non-Congress (I) ruled States would make a hue and cry in the Press and other media that the State Governments are diverting their funds for other purposes. Therefore, avoidable friction takes place between the Centre and the States, especially when there are twelve States ruled by non-Congress (I) parties. Therefore, I would like to make a suggestion. As I said, every year, two-thirds or half of the population in the country is affected by natural calamities. Therefore, it is not possible for the State Governments alone to meet the situation. It is not justifiable also. These are national calamities. When half of the population is involved, it is a national calamity. It is the duty of the nation, it is the duty of the Centre, to come to the rescue of the different States.

In 1977, on November 19, the birthday of late Shirmati Indira Gandhi, there was a cyclone in Andhra Pradesh. Thousands of people died. There was a tidal wave in Krishna District. More than 5,000 people died. The Central Government, the State Government as well as international organisations like the W.H.O. , the U.N.I.C.E.F. , the Red Cross etc. , together were not able to provide relief in a proper way. I am referring to this only to point out that when even international organisations were not in a position to give relief to the affected parts, to the affected areas, it is not fair, it is not justifiable, to leave the entire burden to the State Governments. Let the Central Government take it up. Let the nation come to the rescue of the affected people.

Another aspect is that every year, it becomes a common feature that when rains occur at Sahayadri Hills or Triyambakam near Nasik in Maharashtra, every drop of it flows down to Andhra Pradesh resulting in floods in Godavari, Krishna, Khammam and Nalgonda Districts. Godavari is not a tamed river like Krishna. The Government of Andhra Pradesh, for quite a long time, has been pleading with the Union Government for taming the river Godavari by allowing them to construct the Polavaram Barrage. The Chief Minister of Andhra Pradesh has been pleading with the Union Government that the Centre need not allocate any funds but just allow Andhra Pradesh to construct the Polavaram Barrage. By this, we will be able to divert the water from the river Godavari to Krishna. This will also enable us to resolve the inter-State dispute and Telugu Ganga canal can have sufficient water, but unfortunately, the Central Government is not taksng a serious view of this.

There are at least 15 major and 13 medium projects that are pending clearance. If all of them are cleared and constructed I think this water crisis shall not

be there. Even some of the water would have been saved and utilized for irrigation purposes in Andhra Pradesh for the entire year.

Dr. K.L. Rao, who was the Minister here and who hails from Andhra Pradesh, had suggested for linking the Ganga and the Kaveri rivers. If both the rivers are linked up, the irrigation problem of this country would be solved permanently. So, instead of going in for piecemeal arrangements or relief measures, let the Government take it up to link the Ganga and the Kaveri rivers and irrigate the entire country to produce more and more.

Sir, neither the Prime Minister nor Shri Bhajan Lal has visited Andhra Pradesh. Whenever any small incident takes place in Andhra Pradesh, the Prime Minister and other Ministers rush to that place. They criticise the State Government. I would like to appeal through you to the Government of India, let the Minister go to Andhra Pradesh, let Shri Bhajan Lal have an aerial survey and see what is happening in Andhra Pradesh. Let the Prime Minister go to Andhra Pradesh and announce immediate relief measures there.

The other thing is, due to deforestation and destruction of forests, all these floods and droughts are taking place. According to the satellite imagery we are having just 8 per cent of the pucca forests in the country. Let some measures be taken so that we can improve the forests. As recommended by 1952 document, at least 33 per cent of the geographical area in this country should be forest-covered and the same is the national forest policy of 1988. To achieve this objective of the national policy, what steps is this Government taking, I would like to know. So it is not sufficient just to change the name from National Wasteland Development Board to echnical mission of Mr. Sam Pitroda. It s not sufficient. So, you should take some concrete measures to encourage afforestation in this country. This does not mean hat you should encourage plantation of ucalyptus and subabul only. They are of to use, they do not serve any purpose.

The other aspect is, there is the need for systematic studies in river morphology and for formulating projects for flood control in this country, more so on river Godavari and river Krishna. Afforestation and water conservation for wasteland development is needed.

Lastly, whenever floods take place, it is natural that cholera and other infectious diseases will spread. Sufficient measures should be taken to innoculate children and other people in the affected parts.

I would like to seek clarifications on these points.

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया उसके लिए आपका आभारी हूं और पहले ही धन्यवाद बताता हूं । अभी-अभी आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, केरल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक राज्यों में जो बाढ़ आई है उसके बारे में कृषि मंत्री ने जो स्टेटमेंट दिया हैं उसको सुनकर कुछ बातें जेहन में आती हैं वह पूछना चाहता हूं। पहला यह कि इस साल हम लोगों ने सुपर कम्प्यूटर लगाया है जो मीटियोरोलोजिकल फोरकास्ट करता है, उसने क्या इस साइक्लोन के बारे में और इस बारिश के बारे में कितने दिन पहले फोरकास्ट किया था ? जो साइक्लोन आना था उसकी डेंसिटी क्या थी और उसकी डेंसिटी को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने क्या कोस्टल एरिया में वार्निंग्ज भेजी थीं ? अगर वार्निंग्ज भेजी थीं तो हमने क्या-क्या प्रीकाशनरी मेसर्ज लिए थे और किन-किन इलाकों से लोगों को हटवाया गया था ? दूसरा , यह इतनी बड़ी तादाद में जो तूफान और बाढ़ का प्रकोप हुआ है, यह प्राकृतिक प्रकोप हैं और हम इसे एक राष्ट्रीय आपत्ति समझ कर इस पर कुछ विचार करें तो अच्छा रहेगा । यहां पर कई लोगों ने अपने विचार रखे, कई लोगों ने अपनी पार्टियों के विचार रखे, कई लोगों ने अपने राज्यों के विचार रखे । परन्तु केन्द्र सरकार एक गार्जियन के रूप में हैं और जैसा कि कृषि मंत्री महोदय ने कहा कि स्टेट गवर्नमेंट के मेमोरेंडम आने के बाद केन्द्रीय टीम

[श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया]

जा सकेंगी । तो मेरा अनुरोध है आपके माध्यम से, कि ऐसा क्यों सोचा जा रहा है, जब आपत्ति का समय है, स्टेट गवर्नमेंट भी वहां पर जूझ रही है इस आपत्ति से, तो उनके मेमोरेंडम आने के पहले केन्द्र सरकार की टीमें वहां जानी चाहिए । कृषि मंत्री महोदय इन राज्यों का दौरा कर सकें, कृषि मंत्रालय के दूसरे आफिसर जाकर दौरा कर सकें और जायजा ले सकें कि इस विपत्ति के वक्त किस तरह की मदद वहां पहुंचाई जा सकती है । इसके साथ-साथ मैं आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि प्रधानमंत्री महोदय भी अपने और कामों को छोड़कर इन विपत्तिग्रस्त इलाकों का दौरा करें । वहां पर किस तरह से अनुदान जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सकता है, इसके लिए कोशिश करने की जरूरत है ।

महोदय, मैं बिहार का रहने वाला हूं और हर साल हमारा राज्य बाढ़ से ग्रसित होता है । बाढ़ के बारे में मेरा जो अपना एक्सपीरियन्स है, वह बताता है कि बाढ़ के वक्त पानी के साथ-साथ जो दूसरी चीजें आती हैं, उनके लिए हमें तैयारियां रखनी हैं । बाढ़ तो एक बार आती है, पर जो पानी जम जाता है, वह जल्दी नहीं निकलता, उस पानी को निकालने की व्यवस्था नहीं है । तो जरूरी है कि देखा जाय कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकारें ऐसे पानी को किस तरह निकालेंगी ।

महोदय, दूसरा यह बाढ़ें बीमारियां लाती हैं, कोलरा फैलता है, जानवर मरते हैं, तो उनके लिए आप क्या करेंगे ? मनुष्य के लिए तो डाक्टर, नर्सेज, दवाइयां भेजेंगे जरूर, लेकिन मवेशियों को बचाने के लिए वेटनरी डाक्टरों का बंदोबस्त करने की जरूरत है । इसके साथ-साथ घर बह जाते हैं । एक बार मैं एक बाढ़ रिलीफ कैम्प देखने गया, वहां रोटियां बांटनी थीं । मुझे देख कर आश्चर्य हुआ कि उस इलाके में जो लोग थे, उन लोगों ने अपने बदन पत्तों से ढक रखे थे क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं थे, कपड़े उनके बह गए थे, मिट्टी के घर ही बह गए थे, किसी तरह वह तैरकर एक उचित स्थान पर आ गए थे और उनके पास कपड़े नहीं थे । तो दवाइयों के साथ, अनाज के साथ, दूध के साथ कपड़े भेजने की भी बहुत जरूरत है । मैं समझता हूं कि यह जो करोड़ों की फिगर हम बांटते हैं, चाहे राज्य सरकार बांटे या केन्द्र सरकार, यह करोड़ों की फिगर न बांट कर अनाज, दूध, कपड़े आदि के रूप में भेजें, दवाइयों के रूप में भेजें तो वह सही आदमी को पहुंच सकेगा ।

इसके साथ-साथ मवेशियों के लिए जो मुख्य चीज की जरूरत पड़ेगी वह है चारा, उनके लिए चारा नहीं मिलता । मवेशियों को बचाया जा सकता है कहीं ऊपर स्थान पर पहुंचा कर, लेकिन चारा न मिलने के कारण भूखे मर जाते हैं । उनके लिए भी गौर देने की जरूरत है ।

महोदय, हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा कि यह फसल का कितना बीमा हुआ था ? मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहूंगा मंत्री महोदय से, कि जिन-जिन इलाकों में बाढ़ आई है, उन-उन इलाकों में क्या वाकई में राज्यों ने फसल का बीमा करवा दिया था और अगर करवा दिया था तो कितने हद तक वह फसल, जो ग्रसित हुई है, बीमा से कवर्ड थी और उनको पैसा कब तक मिल जाएगा ? इमीजिएट स्टेप्स जो लेने हैं, वे हैं–रिशेड्यूलिंग आफ लोन्स टू फार्मर्स, फ्रेश लोन्स टू द फार्मर्स, मिनिमम रेट आफ इंटरेस्ट एण्ड स्टॉप रेवेन्यू कलेक्शन ड्राइव और भविष्य में जो फ्लड-प्रोन-एरियाज हैं, वहां इंश्योरेंस कंपलसरी की जाय । फार्मर्स के साथ-साथ वहां के लोगों की फसल और मवेशियों की इंश्योरेंस कंपलसरी की जाय ।

इन्हीं कुछ सुझावों के साथ मैं आपसे इजाजत चाहता हूं । धन्यवाद ।

5.00 p.m.

DR. NARREDDY THULASI REDDY (Andhra Pradesh): Respected Vice-Chairman, Sir, these floods coming and going, the honourable Minister making statements,

shedding crocodile tears, and going back to his bungalow, Members participating vigorously in the discussion and wasting their calories, these are all routine. In the last monsoon session we discussed it and again we are discussing it now and in the next monsoon session also we will discuss it. But the people who are affected by the floods do not want all these discussions and shedding of crocodile tears. They want immediate relief.

We are wasting crores of rupees in Sri Lanka, for what? For nothing. But here, hundreds of people died, lakhs of cattle died, lakhs of acres of land eroded, roads destroyed and tanks breached. But the Central Government is shedding only crocodile tears. I want an assurance from the honourable Minister, of immediate relief—not marginal money—in the form of grant of at least Rs. 100 crores to the State of Andhra Pradesh. I want this assurance from the honourable Minister.

My second point is, there should not be any discrimination between Congress (I) ruled States and non-Congress(I) ruled States in the matter of providing assistance. My third point is, the honourable Prime Minister or, at least, the honourable Minister of Agriculture should visit not only Andhra Pradesh but all the flood-affected areas in the entire country. Also, there must be a separate housing policy for those people who are affected. Central Water Commission's clearance should be given to all the pending projects immediately, whether in Andhra Pradesh or any other State. The Garland Canal Scheme or the Ganga-Godavari-Cauvery Scheme, either of these, must be implemented immediately as a permanent measure. Afforestation, social forestry and wasteland development programmes should be immediately implemented most vigorously and effectively.

So, Sir, I want an assurance of assistance from the honourable Minister, not in the form of statements but in the form of immediate assistance by grant of at least Rs. 100 crores to Andhra Pradesh and to other State also. Thank you, Sir.

श्री मंवरलाल पंवार (राजस्थान) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, कृषि मंत्री जी के वक्तव्य के संबंध में मैं चन्द स्पष्टीकरण चाहता हूं और उसके पूर्व दक्षिण भारत के प्रान्तों में प्राकृतिक विपदा से हुई क्षति से हतप्रभ और मृतकों के परिवार जनों के प्रति संवेदना इस सदन के माध्यम से व्यक्त करना चाहता हूं । इसके साथ ही भारत सरकार और प्रधान मंत्री जी को प्राकृतिक विपदा के लिए 204 करोड़ की सरकारी सहायता और प्रधान मंत्री कोष से मृतकों के परिवार जनों को 10 हजार रुपए की सहायता प्रदान करने हेतू धन्यवाद देना चाहता हूं ।

मान्यवर, मैं इस सदन में इस बात को बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि मेरे विपक्ष के भाइयों के मानस में केवल एक आलोचना की ही बात होती है वह इस बात से गलत साबित हो जाती है कि हमारे युवा प्रधान मंत्री जी ऐसी प्राकृतिक विपदाओं के समय में किस प्रकार से हर प्रांत के लिए सहयोग प्रदान करते रहे हैं । वर्ष 87–88 में जिस समय भीषण अकाल पड़ा था उस समय केन्द्र सरकार के द्वारा प्रधान मंत्री जी ने राजस्थान के लिए जो 800 करोड़ की सहायता दी और यह राशि राज्य सरकार ने खर्च की जबकि पिछले 40 साल के अकाल में राज्य शासन ने 600 करोड़ ही खर्च किए । इस तरह जन-धन और पशु-धन को बर्बादी से बचाया । यह है हमारे प्रधान मंत्री की ऐसी प्राकृतिक विपदाओं में राज्य सरकारों को सहायता की बात । फिर भी विपक्ष के भाई कहते हैं कि वह राज्यों के साथ भेदभाव करते हैं, जहां कि कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं है । क्या केरल को, क्या आंध्र प्रदेश को, क्या तमिलनाडु को यह 204 करोड़ का मार्जिन मनी की सहायता मिलने नहीं जा रही है। इस सदन के माध्यम से मैं तो यह कहना चाहता हूं कि विपक्ष की सरकारों को दी जाने वाली सहायता की राशि भी वह खर्च नहीं करते हैं । पश्चिमी बंगाल को दी जाने वाली राशि का भी उन्होंने पूरा उपयोग नहीं किया । इसी प्रकार से मेरे विपक्ष के भाई जब यह

[श्री भंवरलाल पंवार]

कहते हैं कि इसमें भेदभाव बरता जाता है, केन्द्र सरकार कभी इस प्रकार की प्राकृतिक विपदाओं में भेदभाव नहीं बरतती है ।

मैं मंत्री महोदय से एक जरूरी जानकारी चाहता हूं, जसा मेरे भाई अहलुवालिया ने कहा, कि हमारी साइंस और टैक्नोलॉजी की उस कगेटी में यह बात आती है कि जब सुपर कम्प्यूटर के माध्यम से पूर्व घोषणा की जानकारी मिल सकती है तो वह जानकारी क्यों नहीं समय पर वहां पहुंचाई जाती जिससे कि मानवता की क्षति को तो बचाया जा सकता है।

इसके साथ ही मान्यवर, मैं मंत्री जी को यह भी बताना चाहता हूं कि हमारे समुद्र में जो रिसर्च वैसल "सागर कन्या" है, वहां पर जो वैज्ञानिक है, वह पूर्व से सारी जानकारी इक्ट्ठी करती है मौसम के बारे में, वह 6-6 महीने पहले की जानकारी इक्ट्ठी करती है और भेजती है राज्य सरकारों को और केन्द्र सरकार को भी, लेकिन उस जानकारी का आगे तक उतना उपयोग नहीं किया जाता है। क्या कृषि मंत्री जी इस संदर्भ में भी हमें बताएंगे ?

इसके साथ ही हमारा यह अनुभव है कि कृषि मंत्रालय, मौसम विज्ञान मंत्रालय और दूसरे मंत्रालयों का आपस का समन्वय किस प्रकार से वह करते हैं, क्या कोई को-आरडिनेट आफिसर इस प्रकार से होते हैं जो कि एक दूसरे की जानकारी उन तक पहुंचाए ताकि समय पर सही फायदा में मिल सके।

इसके साथ ही मैं कृषि मंत्री जी से यह भी जानकारी चाहता हूं कि वहां तो आई बाढ़, लेकिन राजस्थान में वर्षा नहीं होने के कारण वहां हानि हो रही है। मैं इन दोनों विपत्तियों को एक साथ कृषि मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं। कृषि मंत्री जी के हस्तक्षेप से यहां से केन्द्रीय टीम भी गई और केन्द्रीय टीम ने भी यह जानकारी हासिल की कि पश्चिमी राजस्थान में अभी तक वर्षा नहीं हुई। इस स्टेटमेंट में माननीय कृषिमंत्री जी ने यह लिखा है कि राजस्थान में भी अधिक वर्षा हुई है। मैं कृषि मंत्री जी को विनम्र शब्दों में कहना चाहता हूं कि यह स्टेटमेंट भ्रामक है। मैं जिस क्षेत्र से आता हूं वहां पीने का पानी भी अभी तक उपलब्ध नहीं है। वहां दिन में केवल 15-20 मिनट पानी नल में आता है और वह भी गहरा गड्ढा खोदकर आता है। जलस्तर करीब 400 फुट नीचे चला गया है। तो ऐसी स्थिति में इस प्राकृतिक विपदा को भी आप जानकर, यह जो टीम आपने हमारे वहां भेजी है इसको भी उसी श्रेणी में, हमें मार्जिन मनी के रूप में राजस्थान को भेजने की आवश्यकता है।

मैं इस सदन के माध्यम से स्वयं सेवी संस्थाओं से भी यह कहना चाहूंगा कि जिस प्रकार सदैव ऐसी विपत्तियों में वह स्वयं आगे आती है, इस समय भी आगे आकर सरकार को सहयोग दें और यह कृषि के क्षेत्र में जो क्षति हुई है, उसके लोन वगैरा की रिकवरी के संबंध में भी सरकार ध्यान दे और खादा वगैरह भी समय पर पूरा पहुंचाने ध्यान दे। धन्यवाद।

श्री धर्मपाल : उपसभाध्यक्ष जी, यह जो 23 जुलाई से 25 जुलाई तक भयंकर बाढ़ आई है और ज्यादा बारिशों से आठ रियासतों में काफी नुकसान हुआ है। जैसा कहा और जो फिगर मंत्री जी ने यहां पेश किए, यह ना-मुकम्मिल हैं क्योंकि अभी रियासती सरकारों से डिटेल उन्हें नहीं मिल सकी है, लेकिन लगता है कि सबसे ज्यादा नुकसान महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल में, जो फिगर हैं उनके अनुसार, हुआ है। बाकी प्रदेशों में भी चाहे तमिलनाडु है, बिहार का कुछ हिस्सा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का भी कुछ नुकसान हुआ है तो अगर हमें यह इंतजार करेंगे कि रियासती सरकारें मैमोरेंडम देंगी और फिर सेंट्रल टीम जाएगी तो उसमें तो समय लगेगा। हमारा तजुर्बा यह है कि दो-तीन महीने बाद स्टेट सरकार मैमोरेंडम भेजती है, फिर सैंट्रल टीम जाती है, जो नुकसान असल होता है, वह दिखाई नहीं देता है। जिन रियासतों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वहां आप सेंट्रल

टीम भेजते हैं और यह अफसरों पर निर्भर करता है कि वे क्या ऐसेसमेंट देते हैं चाहे वह कांग्रेस सरकार हो या नान-कांग्रेस सरकार हो, वे फिगर्स को इनफ्लेट करते हैं अगर नुकसान सौ करोड़ का हुआ है तो चार सौ करोड़ बताते हैं ताकि ज्यादा पैसा मिले। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि जो राहत मिलनी चाहिए वह पूरी न मिले।

महोदय, पिछले सालों में जो भयंकर सूखा पड़ा सदी का, जिन इलाकों में ऐसी स्थिति हुई वहां हमारे प्राइम मिनिस्टर और ऐग्रिकल्चर मिनिस्टर साहब गए। उससे स्टेट गवर्नमेंट की मशीनरी ऐलर्ट हो गई। तो इससे एक टेंटेटिव फिगर थोड़े दिनों में मिल सकती है और जो इनका मैनेजमेंट ग्रुप है वह संपर्क रखे सरकारों से तो टेंटेटिव जो नुकसान हुआ है उसको एसेस करके फौरी मदद उनको मिलनी चाहिए।

महोदय, यह भी दुरुस्त है कि हमारे कुछ नार्म्स हैं, लेकिन यह रियासत का नान-प्लान गैप इतना है, राज्य सरकारों की पोजिशन यह है कि वे तनख्वाह भी नहीं दे सकते। जो नान-डेवलपमेंट प्लान का पैसा है उसको नेचुरल कैलैमिटी पर खर्च नहीं कर सकते। उसके लिए राज्य सरकार को दिल खोलकर मदद करनी पड़ेगी।

जहां तक राशन का सवाल है, केरल और आंध्र प्रदेश को जहां लोग ऐफेक्टेड हैं उनकी खसूसी मदद करनी चाहिए चाहे चावल की हो, दवा की हो, तजुर्बा हमारा यह है कि फलड के राहत का सामान जिसका नुकसान हुआ है उसको नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए कमेटियां बननी चाहिए जिनमें लोगों के चुने हुए नुमाइंदे हों। यह इंसानी मसला है, जैसा अभी कुछ साथियों ने यह उभारा कि कुछ हुआ नहीं है, यह सही नहीं है। केवल दो रियासतों को 8 करोड़ रुपया दिया गया। जहां बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, उसके लिए लांग टर्म और शार्ट टर्म इंतजाम होने चाहिए। जहां कुए निकाल सकते हों वहां इरिगेशन के लिए जैसे राजस्थान में खोदने पड़ें, गुजरात में खोदने पड़ें, तो इससे सैकड़ों करोड़ रुपया जो हमारा रिलीफ की शक्ल में जाता है, वह परमेनेंट ऐसेट्स के रूप में बन सकते हैं लांग टर्म और शार्ट टर्म प्लानिंग से। मैं चाहूंगा कि पैसा समय पर दिया जाए। यहां सी.ए.जी. का बहुत जिक्र हुआ और कहा गया कि जो पैसा आंध्र प्रदेश को सैलाब के लिए दिया था उसको मिसयूज हुआ। हमारा मकसद यही है कि जिस मकसद के लिए मदद दी जाए वह उसी पर खर्च हो। जिसको मदद मिलनी चाहिए उसी को मदद मिले। यह कृषि मंत्रालय के मैनेजमेंट ग्रुप का काम है कि वह देखे कि ऐफेक्टेड आदमी को रिलीफ मिलती है या नहीं। इसके लिए कमेटियां बनानी पड़ेंगी, क्योंकि सरकारी मशीनरी के भरोसे पूरी मदद मिलेगी; यह नामुमकिन है।

दूसरा मेरा कहना है कि मानसून अच्छा हुआ है, इससे नुकसान भी हुआ है लेकिन फायदा भी देश को हुआ है, अनाज की पैदावार बढ़ेगी तो इसमें कृषि मंत्रालय को ध्यान रखना चाहिए कि सेंट्रल टीम भेजकर फौरन नुकसान का सही जायजा लेकर लोगों को मदद दी जाए। जो पैदावार नष्ट हो गई है, जहां पानी है, वहां फसल लगाने के लिए खाद, चाहिए, बीज चाहिए, उसके लिए बैंक से कर्जा चाहिए तो यह देखना चाहिए कि उसको लांग टर्म लोन बैंक से मिल सके ताकि वह खाद और बीज ले सके और अपनी फसल बो सके। तो मैं चाहूंगा कि सही वक्त पर रिलीफ दी जाए। अगर रिलीफ 6 महीने बाद देंगे तो उसका कोई मकसद नहीं है। यह ठीक है कि प्रधान मंत्री ने 40 लाख रुपये दिए हैं। यह ज्यादा से ज्यादा 400 लोगों को मिल जायेंगे और आपकी फिगर है 586। इसलिए आपको और पैसा दे देना चाहिए। यह तो प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से दिया गया है। राज्य सरकारों का भी फर्ज

(श्री भंवर लाल पंवार)

गया है। राज्य सरकारों का भी फर्ज हो जाता है कि वह अपनी तरफ से भी मदद करे क्योंकि पूरी मदद तो मरकजी सरकार दे नहीं सकती। एक बार यह फैसला होना चाहिए, यह नार्म्स आप बनायें कि राज्य सरकार कितना पैसा दे, मर्कजी सरकार कितना पैसा दे। जब नेचुरल क्लेमिटी हो, जब ऐसी बाढ़ आए--सूखा पड़े तो कितनी मदद मरकजी सरकार करेगी और कितनी स्टेट सरकार को करनी चाहिए। इस लिए आपको नार्म्स बनाने चाहिए। अगर किसी की फसल बह जाती है, तबाह हो जाती है, खराब हो जाती है पर-एकड़ तो आप कितनी मदद कर सकते हैं यह आपको देखना होगा। क्योंकि हरेक स्टेट में तो शायद क्राप्स इंश्योरेंस लागू नहीं है। केरल के भाई ने जैसा कहा 4 हजार मकानों को नुकसान हुआ है जिसमें 1500 बिल्कुल खत्म हो गए उनके लिए टेंट वगैरह का इंतजाम करना चाहिए। स्टेट सरकार पूरी तरह से इंतजाम नहीं कर पाएगी। इसके लिए आपको भी मदद करनी है। जिनके मकान नहीं रहे उनके लिए झोपड़ी, टेंट वगैरह का इंतजाम होना चाहिए। उनकी फसल का नुकसान होता है, उनके मवेशियों का नुकसान होता है तो कैसे पूरा करेंगे इसके लिए अगर कोई नार्म्स होंगे कि मरकजी सरकार इतनी मदद देगी और राज्य सरकार इतनी मदद देगी तो सही तरीके से उन का सब इंतजाम हो सकेगा। इसके साथ पूरे हाउस की हमदर्दी है। मैं भी उसमें शामिल होता हूं। जिन लोगों की जानें गयीं, फसल का नुकसान हुआ, मवेशी मारे गये उनकी मदद के लिए हमारे प्रधान मंत्री जी ने अपने रिलीफ फंड से मदद दी है। उनका बड़ा खुला दिल है। उन्होंने इसे पालिटिकल क्वेश्चन नहीं माना है। एक नेशनल क्वेश्चन लेकर काम किया हैं। वह खुद जायेंगे। वक्त निकाल कर कृषि मंत्री जी भी जायेंगे। लोगों की हमेशा कांग्रेस के साथ हमदर्दी रही है चाहे कांग्रेस स्टेट्स हों या नान कांग्रेस स्टेट्स हों। कांग्रेस स्टेट्स के लोग तो देख ही रहे हैं साथ ही नान कांग्रेस स्टेट्स के लोग भी हमारी तरफ देख रहे हैं। वक्त आने वाला है वह हमें वापस उधर लायेंगे। इधर तो हम हैं ही। शुक्रिया।

श्री भजन लाल: माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो यहां पर अपने विचार रखें उनके साथ सारा सदन सहमत है। आप जानते हैं पिछले दो दिनों में देश में बाढ़ से काफी तबाही हुई है। सभी महानुभावों की उनके साथ बेहद हमदर्दी है। लेकिन आप जानते हैं कि अचानक कोई आपदा आ जाए तो उसका मुकाबला सरकार और देश के लोगों को बहादुरी के साथ करना चाहिए। सब को बड़ा भारी दुख है। बहुत सी जानें गयीं, पशु भी मारे गये, फसल का भी बहुत नुकसान हुआ है। हर तरह से बर्बादी हुई है। इसके लिए भारत सरकार बड़ा भारी चिन्तित है। इसी बात को सामने रख कर मैंने यह सब आपके सामने रखा। जैसा मैंने कहा आंकड़ों में थोड़ा बहुत अन्तर हो सकता है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने बोलते हुए कहा कि अखबारों में बहुत ज्यादा आया है, रेडियो में कुछ और आया है और सरकार की तरफ से आंकड़े कुछ बताये गए हैं। अभी तक जो सूचना हमारी तरफ से प्राप्त हुई है, सरकार की तरफ से प्राप्त हुई है वह मैंने आपके सामने रखी है। इसमें छिपाने की कोई बात नहीं है। छिपाने की बात तब हुआ करती है जब सरकार का दोष होता है। उस वक्त थोड़ा बहुत छिपा ले तो बात समझ में आ सकती है। इस में किसी का दोष नहीं है। यह प्रकृति का दोष है और इसमें किसी का बस नहीं चल सकता। लेकिन इंतजाम बस जरूर चलता है, जैसा अभी बहुत से माननीय सदस्यों ने बोलते हुए कहा कि जो हमारा सुपर कम्प्यूटर है इसने पहले से क्यों नहीं चेतावनी दी। इसको पहले से बताना चाहिए था। सुपर कम्प्यूटर ने इसके बारे में हम को पहले बताया था। लेकिन आप जानते हैं कि सही सूचना और वह भी बहुत पहले सुपर कम्प्यूटर भी दे नहीं सकता। वह चौबीस घंटे में, अगले चौबीस घंटों में क्या होने वाला है यह तो बता सकता है लेकिन एक सप्ताह पहले कुछ बताने

हैं तो वह बहुत एकुरेट, बिलकुल ही सही बैठता हो, ऐसा नहीं है, अभी तक जहां तक हमने महसूस किया है, यह स्थिति है। चौबीस घंटे पहले बकायदा मौसम विभाग ने इस बात की घोषणा की थी कि इन इन एरियाज में बहुत भारी वर्षा होगी और उनका कहना है कि यह गलत साबित नहीं हुआ और चेतावनी भी दी। आप जानते हैं कि रेडियो और टी.वी. से ही चेतावनी दे सकते हैं। घर घर जाकर तो यह नहीं दी जा सकती है क्योंकि समय थोड़ा होता है। जब रेडियो और टी.वी. से चेतावनी दी जाती है तो राज्य सरकारों का भी कुछ कर्तव्य हो जाता है कि वे लोगों को बतायें और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बारे में कुछ कंट्रोल करना चाहिए लेकिन सारी चीजें एकदम से कंट्रोल होना संभव नहीं है। चाहे कहीं कांग्रेस की सरकार हो या गैर कांग्रेसी सरकार हो, सब के साथ यही स्थिति है। किसी को अगर कहा जाय कि आज सुबह यह होने वाला है तो कोई उठने के लिए तैयार नहीं है। रेडियो, टी० वी० पर जो कुछ बताया जाता है या कम्प्यूटर जो बताता है लोग समझते है कि वह सच भी होगा या नहीं। बहुत से लोग उठने की कोशिश भी नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने हमेशा चाहे कहीं सूखा पड़ा हो या बाढ़ आई हो, हर तरह से बगैर किसी भेदभाव के सारे देश के लोगों की पूरी सहायता की है। एक दो माननीय सदस्यों ने कहा कि जहां पर गैर कांग्रेसी सरकारें हैं वहां सहायता कम दी जाती है और जो कांग्रेसी सरकारें हैं वहां सहायता ज्यादा दी जाती है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि 1987-88 में जब इस देश में सूखा पड़ा था तो 1444 करोड़ रुपये दिये गये थे। बगैर किसी भेदभाव के यह रुपया बांटा गया था। आन्ध्र प्रदेश को एक साल में 95 करोड़ रुपये दिये गये थे। इसी तरह से गुजरात और राजस्थान को जहां पर सबसे ज्यादा सूखा पड़ा था, लगातार तीन-चार साल तक सूखा पड़ा था, वहां पर गुजरात को 282 करोड़ रुपये दिये गये थे। हरियाणा को भी दिया गया। सूखे की वजह से कितना नुकसान हुआ है उसी के हिसाब से पैसा दिया जाता है। हरियाणा को 37 करोड़ रुपये दिये गये। कर्नाटक को 47 करोड़ रुपये दिये गये और केरल को भी 47 करोड़ रुपये दिये गये और कुछ जो छोटे प्रदेश उनको थोड़ा पैसा दिया गया। नुकसान के हिसाब से हमने पूरी मदद हर प्रदेश को देने की कोशिश की है। इसमें कांग्रेस की सरकार हो या कोई दूसरी सरकार हो, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। इसी तरह से पिछले साल बाढ़ आई तो 570 करोड़ रुपयों की सहायता दी गई। आन्ध्र प्रदेश को 28 करोड़ रुपए दिए गए और अरुणाचल प्रदेश को 6 करोड़ रुपये दिए गए और असम को 85 करोड़ रुपये दिए गए। इसमें किसी प्रदेश का कोई सवाल नहीं है चाहे किसी भी पार्टी की सरकार क्यों न हो। ..(व्यवधान) हरियाणा को भी दिया गया। हरियाणा को असम के मुकाबले बहुत कम दिया गया अर्थात् 32 करोड़ रुपये दिए गए। इसमें प्रदेश या दिल्ली का सवाल नहीं है। इसमें सवाल यह है कि नुकसान कितना हुआ है। आप कहते हैं कि हरियाणा को ज्यादा दे दिया और श्री देवी लाल कहते हैं कि कम दिया है और कहते हैं कि भारत सरकार हरियाणा के साथ भेदभाव करती है, यह एलीगेशन लगाया जाता है। इसमें किसी प्रकार के भेदभाव का कोई सवाल नहीं है।

SHRI ASHIS SEN (West Bengal): The question, the issue, under discussion here is the flood situation.

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: We are discussing now about the floods in Maharashtra, Andhra Pradesh, Kerala and Orissa, not about Haryana.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let the Minister give his reply.

श्री भजन लाल: मैं अभी बता रहा हूं, आप सुनने की तो कृपा कीजिये। ...(व्यवधान)

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: There is no flood in Haryana!

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Kindly hear the Minister's statement first.

श्री भजन लाल : मैंने खुद कहा कि किसी के साथ कोई भेदभाव का सवाल नहीं है । इस देश में आप जानते हैं कि प्रजातंत्र है और जो भी सरकार सेंटर में बैठी है उस सरकार का कर्तव्य बन जाता है कि प्रजा की तकलीफ को दूर करे । जो भी लोगों की समस्या है उस समस्या का समाधान करे । इसके लिए आप जानते हैं कि कुछ नार्म्स बने होते हैं और उसके मुताबिक हर प्रदेश की पूरी सेवा की जाती है । जैसा मैंने अभी बताया कि असम जैसे प्रदेश को 85 करोड़ रुपए दिये हैं । इसके साथ ही उस प्रदेश को बाढ़ से बचाने के लिये और भी कुछ काम करने होते हैं उसके लिये भी हम प्रदेश सरकारों को पैसा देते हैं । जैसा कि अभी एक माननीय सदस्य ने यहां पर कहा कि साहब हर साल बाढ़ आती है इसके लिए भारत सरकार ने क्या इंतजाम किया है । हम बाढ़ से बचाने के लिए पैसा स्टेट्स को देते हैं । लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स उसको ठीक से खर्च नहीं करतीं और बजाय उसको इस काम पर खर्च करने के कहीं और खर्च कर देती है । बहुत से प्रदेशों में पैसा बाकी बच जाता है । सोमवार या मंगलवार को जब मैं आपसे बात करूंगा तो मैं आपको बता दूंगा कि हमने किस प्रदेश को कितना पैसा दिया । बाढ़ के लिये कितना पैसा दिया, सूखे के लिये कितना पैसा दिया । किस प्रदेश से कितना खर्च किया और कितना खर्च नहीं किया । मैं आंकड़े भी ये आपको बताऊंगा । लेकिन यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि हर प्रदेश को बगैर किसी भेदभाव के बाकायदा उनकी जरूरत के मुताबिक पैसा दिया जाता है अब मैं आपके सामने केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात करना चाहता हूं । हमने केरल को 10, कर्नाटक को 15 और महाराष्ट्र को 21 करोड़ रुपए पिछले साल दिया । यानी इस तरह से 570 करोड़ रुपए हमने सारे मुल्क में जहां कहीं भी ऐसी स्थिति आई, दिए । एक माननीय सदस्य ने कहा कि पंजाब को आपने ज्यादा दे दिए । आप जानते हैं कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश ये तीन प्रदेश ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा अनाज पैदा करते हैं ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : सवाल यह नहीं है सवाल यह है कि इन राज्यों ने कितना पैसा मांगा और आपने कितना पैसा दिया ।

SHRI P. K. KUNJACHEN: It is very meagre. That is what he says... *(Interruptions)*...

श्री भजन लाल : मैं उस प्वाइंट पर आता हूं । पंजाब ने जो मांगा है वह 857 करोड़ रुपये मांगे और हमने 150 करोड़ रुपये उनको दिए ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : इसी तरह से हम जानना चाहते हैं कि दूसरे राज्यों ने क्या मांगा और आपने क्या दिया ?

श्री भजन लाल : आंध्र प्रदेश ने 271 करोड़ रुपया मांगे और हमने उनको दिये, 28.76 करोड़ । पंजाब को 857 में से 150 और आंध्र को 271 में से 29 करोड़ । बल्कि यह कुछ फालतू बैठाता है रेशियो के हिसाब से । आप हिसाब लगा लीजिये । इसी तरह असम को हमने 85 करोड़ रुपये दिये । लेकिन यह 85 करोड़ रुपया उन्होंने पूरा खर्च नहीं किया । वेस्ट बंगाल को 38 करोड़ रुपये दिये । इसी तरह से केरल को भी है ।

SHRI SUNIL BASU RAY (West Bengal): When did you pay? Tell me when you paid. You did not pay in time.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Kindly hear the Minister first. Let him reply. Do not interrupt his reply. Members have sought clarifications. Why are you preventing the Minister from replying?

श्री भजन लाल : आप जरा बात सुनिये । जो मुद्दा उठाया है उसकी बात मैं कर रहा हूं । किसी भी प्रदेश

के साथ भेदभाव का सवाल नहीं है । जब भी इस संबंध में कोई सूचना मिलती है तो सारे के सारे भारत सरकार के अधिकारी उस काम पर जुट जाते हैं, मंत्री और प्रधानमंत्री जी भी । आप जानते हैं कि कल ही पता चला कि इतने लोगों की मौत हो गई । माननीय सदस्य धर्मपाल ने ठीक ही कहा है कि कुछ पैसा कम दिया गया, लोगों की जानें ज्यादा गई हैं यह ठीक बात है कि कल की सूचना 400 से कम की थी लेकिन आधी रात को पता लगा कि 400 से ज्यादा 584 लोगों की मृत्यु की जानकारी मिली । 40 लाख रुपया कल दोपहर की सूचना के मुताबिक दिया गया था । जितने लोगों की सूचना थी उसके मुताबिक दिये गये थे । इतने लोग मरे हैं इसका हमें बहुत खेद है, बहुत दुख है और 10 हजार रुपये की राशि इतनी बड़ी राशि नहीं है । लेकिन फौरी सहायता के तौर पर प्रधान मंत्री जी ने अपने सहायता कोष से हर एक मरने वाले परिवार को 10 हजार रुपये दिये हैं । ताकि फौरी तौर से उनको मदद हो जाए । कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि हवाई जहाज दुर्घटना में मरने वालों को एक लाख रुपया मिल जाता है । हवाई जहाज में जब आदमी बैठता है, उनको इस बात की भी जानकारी है कि उनका बाकायदा टिकट के अन्दर बीमे का प्रिमियम शामिल होता है बीमे के पैसे टिकट के अन्दर वसूल कर लिये जाते हैं । तब पैसा देते हैं । यह नहीं कि वैसे ही किसी को देते हैं हवाई जहाज वाले । बीमे का प्रिमियम उसके अन्दर शामिल है ।

डा० रत्नाकर पाण्डेय : कामनसेंस की कमी है ।

श्री भजन लाल : यही नहीं उसके साथ साथ भारत सरकार की तरफ से अलग से पांच हजार रुपये की मदद अगर कोई भाई मर जाए तो करते हैं । कोई अंगहीन हो जाए तो 2500 रुपये की मदद करते हैं स्टेट गवर्नमेंट्स भी कहीं 10 हजार, कहीं 20 हजार, कहीं पांच हजार अपने अपने बजट के हिसाब से जो पैसा उनके पास अवेलेबल होता है उनकी मदद करती हैं । स्टेट गवर्नमेंट्स भी बाकायदा मरने वालों की मदद करती हैं । पशु जो मर जाते हैं उनके लिए भी बाकायदा नार्म बने हुये हैं । मार्जिनल किसान का पशु मर जाए तो उसको 33 प्रतिशत देते हैं, छोटे किसान को 25 प्रतिशत देते हैं । मकान गिर जाए तो मकान के लिए एक हजार रुपये देते हैं । कच्चे मकान के लिए पांच सौ रुपये देते हैं । मरम्मत के लिए भी सहायता करते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि यह राशि कोई बहुत बड़ी राशि नहीं है क्योंकि एक छोटा सा मकान अगर गिर जाए तो भी एक हजार रुपये की सहायता का कोई मतलब नहीं है (व्यवधान) भारत सरकार की तरफ से हम इतनी मदद करते हैं लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को भी चाहिये कि वह और सहायता करे लेकिन हम अपने नार्म के मुताबिक जहां भी बाढ़ या सूखा आ जाता है पूरी सहायता भारत सरकार की तरफ से हम करते हैं । अब मैं जिन माननीय सदस्यों ने मुद्दे उठाये उनको बताना चाहता हूं । सब से पहले पुगलिया साहब ने यह कहा कि सर्वे टीम शीघ्र भेजें । जहां तक सर्वे टीम का ताल्लुक है हमने फैसला लिया है इस बात के लिए ज्यों ही बाढ़ की सूचना मिले या ऐसी कोई अन्य आपदा आ जाए या ओले पड़ जाएं या बीमारी फैल जाए तो स्टेट गवर्नमेंट को हम कहते हैं कि फौरन हमारे पास ज्ञापन भेजे । ज्यों ही स्टेट गवर्नमेंट का ज्ञापन आता है हमने यह फैसला कर रखा है कि एक हफ्ते के अन्दर हम टीम भेजते हैं । सात दिन में वह टीम उसकी रिपोर्ट देती है और बाकायदा सात दिन में एक हाई पावर कमेटी की मीटिंग होती है और अगले सात दिन में फैसला ले लिया जाता है यानी 21 दिन, ज्यादा से ज्यादा 30 दिन से फालतू लगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है । 30 दिन में बाकायदा पैसा दे दिया जाता है । एक दो माननीय सदस्यों ने यह बात कही कि टीम भेजने की आवश्यकता नहीं है । पहले पैसा दे देना चाहिये । आप जानते हैं कि जब बहुत बड़ी मुसीबत आती है तो पहले भी देते हैं । अभी 204 करोड़ का सवाल था । वह 204 करोड़ रुपया

[श्री भजन लाल]

नहीं है । सारे देश में हमने 339 करोड़ रुपया मार्जिन मनी स्टेटों के पास रखा हुआ है । जहां कहीं भी ऐसी आपदा आ जाए जहां कहीं बाढ़ आ जाए सूखा पड़ जाए तो स्टेट गवर्नमेंट के पास मार्जिन मनी है वह खर्च कर सकती है उसको पूरा अधिकार है । पिछले साल हमारे पास जो मार्जिन मनी थी वह 240 करोड़ रुपया थी । इस दफा हमने 100 करोड़ रुपया और बढ़ाया है सारे मुल्क के लिए ताकि 100 करोड़ रुपया हम स्टेट्स को और दे दें । जहां कुछ कमी भारत सरकार ने महसूस की उनकी मार्जिन मनी को हमने बढ़ाया है । यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय सदस्यों को भेदभाव की शिकायत दूर हो जाए । आन्ध्र प्रदेश के पास पिछले साल मार्जिन मनी 24.50 करोड़ की थी और इस दफा हमने आन्ध्र प्रदेश को 43.25 करोड़ रुपया मार्जिन मनी का दिया है । पिछले साल से तकरीबन दुगुना कर दिया है । दुगुनी मार्जिन मनी हमने किसी भी स्टेट के लिए नहीं बढ़ाई है ताकि आपको किसी किस्म की शिकायत न रहे कि जहां अपोजीशन की सरकारें हैं वहां ज्यादती की जाती है । मैंने इसलिए आपको मिसाल दी है कि पिछले साल 240 करोड़ रुपया था इस दफा हमने उसको बढ़ा कर 339 कर दिया है । यह पैसा प्रदेशों के पास रखा हुआ है ताकि फौरी तौर से वे खर्च कर सकें यही नहीं प्रधान मंत्री जी या मंत्री जी मौके पर जाते हैं । वह महसूस करते हैं कि यहां फौरी सहायता दी जानी चाहिए तो बगैर टीम भेजे, बगैर सर्वे किए हम उनकी सहायता करते हैं ताकि जहां फौरी मदद की आवश्यकता होती है वह मदद पहुंच सके । जैसे पिछली बार आप जानते हैं कि कुछ प्रदेशों में हमने एडवांस सहायता की । चाहे वह वैस्ट बंगाल था, या पंजाब था, या असम था--असम में भी बाढ़ आई तो हमने उनको चालीस करोड़ रुपए की एडवांस सहायता की बगैर ज्ञापन आए उनको, क्योंकि फौरी सहायता देने की आवश्यकता थी उन प्रदेशों में । इसलिए हमने उनको फौरी सहायता भी दी है ।

जो कुछ माननीय सदस्यों ने शंका जाहिर की है, यह शंका नहीं होनी चाहिए । भारत सरकार के दिल और दिमाग में कोई पार्टी की बात नहीं है, देश की बात है, नेशन का सवाल है । पार्टी पालिटिक्स आपके दिमाग में तो हो सकती है शायद, लेकिन जिन्होंने मुल्क चलाना है, उनके दिमाग में कभी पार्टी या पालिटिक्स की बात नहीं आती ।

जहां तक नेशन की सहायता, मानव की सहायता करने का सवाल है, मानव की सहायता करना सरकार का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है, जोकि वह करती है ।

माननीय श्री गुरुपदस्वामी जी ने कहा कि सरकार क्या करेगी ? कृषि मंत्रालय बैठ कर ही मीटिंग करता रहेगा । ऐसी बातें कहना कोई उचित बात नहीं है । बैठ कर सरकार बात नहीं करे, तो यह तो है नहीं कि कोई जादू से अपने आप बात बन जाएगी । ऐसा कोई जादू नहीं है । ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि मंत्र से सब कुछ हो जाएगा और अपने आप सब पहुंच जाएगा, कुछ बात भी करनी पड़ेगी फाइनेंस डिपार्टमेंट से भी बात करनी पड़ेगी, पैसा देने की बात है, कितना नुकसान हो गया, उसकी कैसे पूर्ति करनी है, किस तरह से पैसा भेजना है, कितना पैसा भेजना है, कितना एडवांस भेजना है, कब टीम भेजनी है, यह सारी बातें आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर सहकारिता डिपार्टमेंट बैठ कर तय करता है और आप देखेंगे कि पिछले सालों में कितना सूखा पड़ा और कितना देश में काम हुआ सूखे में । पिछले साल कितनी भयंकर बाढ़ आई, और कितना शानदार काम बाढ़ के बारे में हुआ है ।

इस बात के लिए आपको मंत्रालय को बधाई देनी चाहिए, न कि उसको क्रिटिसाइज आप लोग करें । यह कोई मुनासिब बात नहीं है । काम करने वाले आदमी को अच्छा बताना चाहिए, कोई गलत काम करे तो उसको गलत बतायें, तो कोई तकलीफ नहीं है । लेकिन इतना शानदार काम हुआ है, आप देखते हैं सूखे से भी और बाढ़ से

भी, जिसकी सारे हाउस को सराहना करनी चाहिए, जिससे कि काम करने वालों का हौसला भी बढ़े ।

एक बात उन्होंने कही कि आपत्तिकारी दल को जल्दी मूल्यांकन करना चाहिए, मौके पर जाएं । वह मौके पर जाते हैं, मूल्यांकन करते हैं । जैसा मैंने अभी बताया कि बाकायदा एक टीम जाती है, सारी बातें देखती है ।

फिर उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बहुत भारी तबाही हुई है । सब से ज्यादा तबाही महाराष्ट्र में हुई है, उसके बाद आन्ध्र और फिर केरल में हुई है जैसा कि मैंने स्टेटमेंट में अभी आपको बताया था कर्नाटक में सिर्फ तीन आदमी मरे हैं, कल रात की जो हमारे पास रिपोर्ट है । यह भी इत्तिला है कि पांच-छह आदमी लापता हैं । अगर वह लापता नहीं मिले, तो आठ-नौ आदमी हो सकते हैं कर्नाटक में, लेकिन चाहे एक भी आदमी क्यों न हो, एक भी आदमी मरता है, तो भी उसकी हमको तकलीफ है । लेकिन बाकी प्रान्तों के मुकाबले में कर्नाटक में कुछ कम तबाही हुई है ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी: जी ने कहा कि मार्जिनल मनी आटे में नमक के समान है इसे बढ़ाया जाए । आटे में नमक के समान नहीं है, फौरी सहायता के तौर पर हमने स्टेट्स के पास पैसा रखा हुआ है और जैसा कि मैंने कहा कि जब जरूरत होती है, मांगते हैं तो बाकायदा बगैर टीम भेजे भी पैसा देते हैं, यदि कोई बहुत बड़ी आपत्ति आ जाए तो । शेष टीम आ जाने के बाद तीन दिन के अंदर अंदर सारा पैसा वहां भेजते हैं ।

अब कुछ महानुभावों ने यह भी कहा कि साहब टीम भेजने की क्या जरूरत है ? अब टीम भेजे बगैर नुकसान का क्या अंदाजा लोगे । आप यूं लिख कर भेज दें--मिसाल के तौर पर--मैं किसी को बेईमान नहीं कहता, लेकिन मैं भी हरियाणा का सात साल मुख्य मंत्री रहा हूं । यहां और भी महानुभाव बैठे हैं, जो मुख्य मंत्री रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट के, आप जानते हैं, कुछ थोड़ा सा--मैं यह नहीं कहता कि स्टेट गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ा कर भेजती हों, लेकिन कुछ थोड़ा ज्यादा पैसा मांगने के लिए भारत सरकार को लिखती है । लेकिन भारत सरकार उसको जांच कर देखे नहीं और जितना वह मांगे, उतना दे दे, तो भारत सरकार के पास तो फिर पैसा है ज्यादा बचेगा भी नहीं । फिर कितना भी लिखें स्टेट गवर्नमेंट, उसे देखने की आवश्यकता ही नहीं है ।

श्री जगेश देसाई (महाराष्ट्र) : यह वह इसलिए करते हैं कि यदि वह सो करोड़ लिखेंगे तो आप केवल 25 करोड़ देते हैं । जो वह लिखते हैं, उसके मुताबिक तो आप नहीं देते ।

श्री भजन लाल : इस काम में टाइम लगेगा । आप सब जानते हैं कि सारे प्रदेश वालों को सही लिखना मुश्किल है । शायद कोई सरकार बढ़ा-चढ़ा कर लिखकर भेज दे, यानि लिखदे ज्यादा, फिर देखना जरूरी हो जाता है । जैसा कि किसी ने कहा--लाइसेंस लेना था रिवाल्वर का, और दरखास्त तोप की दे दी उसने कि मुझे तोप चाहिए जब कलक्टर के पास एप्लीकेशन गई, तो उसने कहा कि आपने तो कैसे मांग ली ?

इस पर उसने कहा कि तोप मांगी, जी तो आप मुझे रिवाल्वर का लाइसेंस देंगे । तो इसलिए कुछ स्टेट्स मांगती भी कुछ ज्यादा हैं । इसलिए भारत सरकार को देखना पड़ता है ।

एक माननीय सदस्य ने कहा केरल के बारे में जो नुकसान हुआ उसके लिए बाकायदा हम पूरी मदद करेंगे । उसमें कोई दिक्कत आने का सवाल ही नहीं है ।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी : सैन्ट्रल टीम भेजने के बारे में ?

श्री भजन लाल : इसके लिए अभी मैंने अर्ज किया था कि जो रिपोर्ट उधर से आएगी उसके एक हफ्ते के अन्दर सैंट्रल टीम चली जाएगी और अगर सैंट्रल टीम

[श्री भजन लाल]

के बिना भी अगर वहां बहुत जरूरी हुआ तो हम उनको और पैसा भी देंगे। हमने उन राज्यों को कह दिया है कि यह पैसा जो मार्जन मनी आपके पास रखी हुई है यह खर्च हो जाए तो भी कोई चिंता करने की बात नहीं है। आप अपने पास से भी खर्च करिए और हमारे से उसको री-चार्ज कर सकते हैं आप हमारे से वह पैसा ले सकते हैं ताकि राज्यों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। इसी तरह से कुलकर्णी जी ने राहत के लिए सहायता जो महाराष्ट्र को हमने दी है इन्होंने कहा कि कुछ फालतू देना चाहिए, 50 करोड़ रुपया, इस वक्त मार्जन मनी महाराष्ट्र के पास 13 करोड़ रुपए हैं हमने कहा है कि फौरन उसको खर्च करें और भी जितनी जरूरत होगी वह और देंगे। हमारी कोशिश यह है कि प्रधान मंत्री जी खुद चाहते हैं कि जहां यह तबाही आ गई है, वहां प्रधान मंत्री जी और कृषि मंत्री द्वारा स्वयं जाकर देखने की बात भी है और अभी यह देखना है कि कल या परसों, जिस दिन भी प्रधान मंत्री जी को समय मिलेगा जल्दी से जल्दी वहां जाकर देखेंगे जितनी बार भी देश में तबाही आई है, बाढ़ आई है, चाहे भूकंप आया है प्रधान मंत्री जी, कृषि मंत्रालय और मंत्रिगण सब जगह मौके पर पहुंच करके लोगों के दुख में साझीदार बने हैं और हमेशा हमने पूरी मदद करने की कोशिश की है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (उत्तर प्रदेश) : यह तो आसाम में बहुत दिनों से आया हुआ है क्या वहां किसी ने चक्कर लगाया है ?

श्री भजन लाल : आसाम के बारे में बाकायदा उनको पैसा दिया है, पैसा उनके पास रखा है और उन्होंने राइस मांगा था वह चावल भेज दिया है। हमारे मंत्री भी वहां पर गए हैं और देखकर आए हैं।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मैं कृषि मंत्री जी से पूछता हूं ?

श्री भजन लाल : आप जानते हैं कि कैबिनेट की साझी जिम्मेदारी है। महाराष्ट्र में चावल की, चीनी की, खाने के सामान की ओर आप जानते हैं कि मैडिकल टीम वगैरह जो-जो भी वहां जरूरत है उसका हमने पूरा इंतजाम किया है ताकि वहां के लोगों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आए।

श्री चित बसु साहब ने कहा कि बाढ़ आने वाले क्षेत्रों में रोकथाम के लिए क्या कार्य किया, जहां पर हमेशा बाढ़ आ जाती है, जैसा मैंने पहले कहा कि बाढ़ आती है तो स्टेट गवर्नमेंट को उसके रोकने का इंतजाम करना चाहिए। भारत सरकार की ओर से उन्हें पैसा देते हैं लेकिन पैसा बहुत सी जगह पर पूरा खर्च नहीं होता अगले साल बाढ़ आ जाती है और पैसा उनके पास बच जाता है।

प्रो० सी० लक्ष्मन्ना (आन्ध्र प्रदेश) : आप एक मिनट सुनेंगे ?

श्री भजन लाल : हां जी।

PROF. C. LAKSHMANNA: Just now you have said that the State Governments should have taken steps to prevent even floods. In this connection, I would like to mention to you that a particular State Government, when there was flood, subsequently wanted to take up the lining of the canals, etc. as a permanent measure. Is it not a fact that the Union Government then said that they cannot take up this unless it was a flood of severest variety and on that pretext you have prevented that particular State Government from taking action on a permanent basis the flood control measures? If that is the case, then what is the basis for you to say today that the State Government should take the measures? Therefore, I would like to know whether it is a fact that the Andhra Pradesh Government was prevented from taking these permanent steps.

श्री भजन लाल : भारत सरकार कभी यह नहीं कहती कि आप बाढ़ की रोकथाम के स्थायी कदम न उठायें।

PROF. C. LAKSHMANNA: Is it a fact or not?

श्री भजन लाल : भारत सरकार ऐसा कभी नहीं कह सकती । हां, मुमकिन है यह हो सकता है कि कहीं किसी जगह पर बांध बनता हो या बांध बनाने की योजना हो तो उस पर कह सकते हैं कि बांध बनने जा रहा है, पैसा खर्च न करें। यह राय दे सकती है लेकिन ऐसा कभी भारत सरकार नहीं कहेगी कि बाढ़ आयेगी तो इसका बंदोबस्त नहीं करिए । आपने कुछ योजनाओं के बारे में कहा कि भारत सरकार के पास ये लंबित पड़ी हुई हैं, पैंडिंग पड़ी हुई हैं । हमारी कोशिश यही होगी कि उन योजनाओं को जल्दी स्वीकृति मिले जिनकी स्वीकृति मिलनी जरूरी है और उनको स्वीकृति मिलनी ही चाहिए । इसी तरह से आपने कहा कि यह काइसेज मनेजमेंट के बारे में कि यह क्या है, चित्त बसु साहब ने कहा। मैंने कहा बाकायदा हमने एडीशनल सेक्रेटरी की अध्यक्षता में एक कमेटी बना रखी है ताकि वह फौरी तौर से जब भी बाढ़ जैसी आपत्ति आती है तो मीटिंग करके, फौरन फैसला ले करके उन प्रदेशों की सहायता करें । श्री चतुरानन मिश्र जी ने सुपर कंप्यूटर के बारे में कहा, जैसा मैंने अभी पहले बताया आपको इसके बारे में कि बाकायदा वह जानकारी देते हैं और एक आपने कहा कि 10 हजार रुपए तो एक मजाक है, हवाई जहाज वालों को एक लाख देते हैं और आपने इसका जवाब मैंने पहले दिया कि यह मजाक का सवाल नहीं है, यह फौरी सहायता की बात है। फसल बीमा योजना का फायदा कितने लोगों को मिला, इन्होंने यह भी पूछा । आप जानते हैं कि फसल बीमा योजना का फायदा उन सभी किसानों को मिलेगा जिन्होंने फसल का बीमा करवा रखा है और फसल का बीमा उन्हीं लोगों का होता है, जिन लोगों ने बैंक से ऋण ले रखा है, अभी तक यह प्रथा है, यह स्कीम ऐसी है, जहां नुकसान हो गया, उन लोगों को बकायदा उसका मुआवजा मिलेगा । लोगों की तरह से जो संस्थायें हैं, उनको वोल्यंटरी तौर से लोगों की सहायता करनी चाहिए यह अच्छा सुझाव है ।

राम चन्द्र विकल जी ने कहा कि रेडियो समाचार पर जो आंकड़े आए हैं उनमें फर्क है । यह बात तो मैं मानता हूं कि कुछ फर्क है; सही जानकारी अभी प्राप्त नहीं हुई है अभी भी जो मैंने कहा इसमें भी फर्क हो सकता है क्योंकि इंटीरियर से भी जानकारी आनी है । मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र से मैं कल से कोशिश कर रहा हूं बात करने की, अभी बात नहीं हो पाई है क्योंकि वह इंटीरियर में गए हुए हैं । जब तक बात नहीं हो जाती, तब तक पूरे आंकड़े सामने नहीं आ जाते । लेकिन जितने हमें उपलब्ध हो सकें, हमने मुनासिब समझा कि हाऊस को इसकी जानकारी देनी चाहिए और हाऊस को जानकारी दी । जब हमारे पास पूरे आंकड़े आयेंगे तो बकायदा यहां लायेंगे और जैसी मैंने खुद पेशकश की, पूरा डिसकशन हाऊस एक बार फिर करे इस बात पर कि क्या-क्या हमने किस प्रदेश की मदद की, किस-किस प्रदेश में कितनी-कितनी जानें गईं, सरकार की तरफ से उनकी क्या-क्या सहायता हुई फलतः, दवाइयों के बारे में खाने के बारे में, राशन के बारे में, फोल्डर के बारे में । हम हर तरह से इसमें पूरी मदद करेंगे ।

श्री राम चन्द्र विकल : मेरा कहना है कि रेडियो भी गवर्नमेंट की एजेंसी है तो उसके और आपके आंकड़ों में फर्क क्यों है ?

श्री भजन लाल : मैं यह वक्तव्य रात को देता तो मैं भी वही देता, जो रेडियो ने दिए ।

श्री राम चन्द्र विकल : यह तो सुबह की न्यूज थी ।

श्री भजन लाल : आप जानते हैं,

[श्री भजन लाल]

रात को, आधी रात को बाद कुछ आंकड़े किए, कुछ बह इकट्ठे किए, मैंने तो आपके सामने तीन बजे कहा है। अब आप रात को रेडियो सुनिएगा तो आपको मिलेगा कि आंकड़े सही नहीं ?

पशुओं के मरने के बारे में कहा गया पशुओं की बीमारी के बारे में कहा गया। हम उसका पूरा इंतजाम करेंगे। बापू कालदातेजी ने कहा कि फोरन टीमें चली जानी चाहिए तो टीमें हम भेजते हैं। राज्यों की मांग के बारे में पूछा कि राज्यों ने मांगा या नहीं तो अभी तक किसी राज्य से भी कोई मेमोरेंडम कोई मांग नहीं आई है क्योंकि सभी इस काम में लगे हुए हैं, इंतजाम में लगे हुए हैं। ज्योंही कोई मांग आएगी, हम फोरन टीम भेजेंगे, फोरन मदद करेंगे और जैसा मैंने पहले कहा कि जहां बगैर टीम के सहायता करने की बात होगी, वहां भी सहायता करेंगे।

मार्जिनल मनी के बारे में मैंने आपको सारा कुछ बताया। राम अवधेश सिंह जी ने कहा, कम दबाव क्षेत्र बना हुआ था और मौसम विज्ञान ने क्या बताया, जैसा मैंने अभी बताया उन्होंने बिहार के बारे में कहा कि हर साल बाढ़ आ जाती है, 102/106 में क्या फर्क है? मैंने बताया कि हम 100 परसेंट को सामान्य मानते हैं, उससे दो-चार-छह परसेंट फालतू भी हो सकता है, दस-बीस परसेंट कम हो जाय तो भी सामान्य मानते हैं, दस-बीस परसेंट ऊपर तक भी उसको सामान्य मानते हैं, थोड़ा सा एक्सेप्ट कह सकते हैं, लेकिन यहां बहुत ज्यादा आ गया, जैसा मैंने पहले आपसे अर्ज किया।

ठाकुर साहब ने कहा कि मौसम की भविष्यवाणी, पूर्व सूचना दी गई। मैंने आपको बताया, इसके बारे में जानकारी दी है। धनराशि बढ़ाने के बारे में भी हमने बकायदा नार्मस के मुताबिक देंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: भविष्यवाणी की क्या जानकारी दी है?

श्री भजन लाल: मैंने कहा न, सुपर कम्प्यूटर 24 घंटे पहले की पूरी सूचना देता है। उसको आप भविष्यवाणी कहेंगे या क्या कहेंगे?

श्री वीरेन्द्र वर्मा: हमें तो आगे की भविष्यवाणी कर दीजिए।

श्री भजन लाल: आगे की भविष्यवाणी बढ़िया रहेगी, आप परवाह मत करिए। बहुत शानदार बारिश होगी सारे मुल्क में। यह जो नुकसान हो गया, इसका दुख है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा: लेकिन इस समय जो मर रहे हैं, उनके लिए क्या है?

श्री भजन लाल: मेडीकल टीम गांव में बाकायदा जा रही हैं। कुछ सड़कें टूट गयीं, कुछ फसलें खराब हो गईं, उसका भी पूरा इंतजाम हम करेंगे। हम मुआवजा देने की कोशिश करते हैं। जब टीम जाएगी, सब चीज देखेगी फसलों के बारे में भी, बाकायदा सड़कों के बारे में भी, सीवेज के बारे में भी, पीने के पानी के बारे में भी। जो भी स्कीम खराब हो जाती है, उनके लिए सहायता भारत सरकार करती है।

हनुमंतराव जी ने कहा कि रिलीफ का काम तुरंत शुरू करवाना चाहिए, जो शुरू हो गया है और कहा बकायदा अच्छा इंतजाम देखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। रामनरेश यादव जी ने कहा कि साधनों का इंतजाम पूरा होना चाहिए। हर तरह से हम पूरा करते हैं। कहा गया— दस हजार रुपए की राशि छोड़ी है। यह तो सहायता के तौर पर है। नारायणसामी जी ने कहा कि महाराष्ट्र के मछुवारे लापता हैं। यह ठीक बात है, मैंने खुद अपने स्टेटमेंट में कहा कि महाराष्ट्र के मछुहारे जो हैं, उनका पता नहीं लेगा है। अभी और जानकारी हासिल करेंगे और आपको पूरी जानकारी हम सोमवार या मंगलवार को हाऊस में देंगे। भोजन आदि का इंतजाम, दवाइयों का इंतजाम, बकायदा इससे सेना की सेवा ली गई है। सरकार पूरी तरह से लगी हुई है। हम मोटर बोट्स और हैलीकाप्टर्स से लोगों को राशन भेज रहे हैं। हवाई जहाज से राशन पहुंचा रहे हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। श्री धर्मपाल साहब ने कहा कि आपका बयान पढ़कर कुछ दुख हुआ। मरने का दुख तो सबको है, लेकिन सरकार द्वारा फौरी तौर से

सहायता पहुंचाने के लिए सरकार की तारीफ करनी चाहिए । जहां तक सड़कें, मकान आदि का नुकसान हुआ है, हम उसका पूरा जायजा लेंगे और लोगों की पूरी सहायता करेंगे । आपने कहा कि कोर्ट में समय बहुत लग जाता है । मैं कहना चाहता हूं कि रिपोर्ट में बिल्कुल समय नहीं लगेगा हम दस दिन के अंदर सारा फैसला कर देंगे । राशन में कटौती का सवाल भी उठाया गया और कहा गया कि सप्लाई बाकी है । जहां सप्लाई की जरूरत है, पूरी की जाएगी । कटौती का सवाल पैदा नहीं होता लेकिन जहां कटौती करने की जरूरत है वहां सरकार कटौती जरूर करती है । मिसाल के तौर पर हरियाणा, पंजाब को ले लीजिए । यहां आवश्यकता नहीं है, इसलिए वहां कटौती भी कर सकते हैं । जहां कटौती करने की जरूरत नहीं है वहां हम बढ़ा कर देते हैं ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान हो ।

श्री जगेश देसाई : महाराष्ट्र का कोटा भी कम कर दिया है । बंबई की दुकानों में राशन नहीं मिलता है ।

श्री भजन लाल : मैं आपसे अर्ज करूं कि देखना यह पड़ता है कि 87–88 में सूखा पड़ा था । आप अगर 87–88 का हिसाब लगाएंगे तो मुश्किल होगी । उस समय भयंकर सूखा था और उसकी वजह से आपको ज्यादा राशन दिया गया । वर्ष 88–89 में बहुत भारी उत्पादन हुआ है और उसे देखते हुए कि कितना मिलना चाहिए, हमने उसी हिसाब से दिया है । . . . (**व्यवधान**) . . .

SHRI P. K. KUNJACHEN: I challenge: Your figure is wrong.

श्री भजन लाल : आप इस बात को समझें कि 87–88 में केरल, वेस्ट बंगाल और उत्तर प्रदेश में अनाज का जितना उत्पादन हुआ उसके बाद 88–89 में ज्यादा हुआ । सब जगह उत्पादन में वृद्धि हुई ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let the Minister complete his reply. Please take your seats. . . . (*Interruptions*) . . .

श्री भजन लाल : उत्तर प्रदेश में रिकार्ड उत्पादन हुआ है । उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल दोनों में रिकार्ड उत्पाद हुआ है । जहां तक केरल का सवाल है, मैं सोमवार-मंगलवार को पूरे आंकड़े दे दूंगा कि 87–88 में कितना उत्पादन हुआ और 88–89 में कितना हुआ ।

श्री राम अवधेश सिंह : आपको आंकड़ों से सुसज्जित होना चाहिए ।

श्री भजन लाल : उत्पादन के बारे में मैं आंकड़ों से साबित करूंगा । मैं कहता हूं कि जितना इस साल 88–89 में हुआ है उतना उत्पादन कभी नहीं हुआ । . . . . (**व्यवधान**) . . . . ऐसा ही वेस्ट बंगाल में है ।

SHRI ASHIS SEN: The question was about the floods. The Minister is utilising this forum for castigating certain States in the matter of food. There is no need to divert the attention of the House.

श्री भजन लाल : जहां तक जमीन को उपजाऊ बनाने का सवाल है, हमने जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए योजनाएं बनायी हैं । पानी से जो जमीन का विनाश होता है, उसे रोककर बांध बनाए जाएं और जहां जमीन ऊबड़ खाबड़ हो तो उसे ठीक करके पानी का इस्तेमाल किया जाए ताकि इस देश में बाढ़ के विनाश को रोका जाय । जहां बाढ़ आती है वहां हम छोटे और सीमांत किसानों को बाकायदा बीज और खाद के पैकिट्स मुफ्त देते हैं और सब्सिडाइज्ड कर के छोटे किसानों की हम मदद करते हैं ताकि किसानों को पूरी मदद दी जाए । . . . . (**व्यवधान**) . . . डा० शिवाजी ने कहा कि राशि समय पर दी जाए । हमने कहा है कि भेदभाव का सवाल नहीं है ।

श्री राम अवधेश सिंह : सहायता कागज पर मिलती है ।

श्री भजन लाल : आपको कागज पर ही लगता है । कुछ लोगों ने कहा कि योजनाएं बीच में पड़ी हैं, उन्हें पूरा किया जाए । हवाई सर्वे किया जाए । . . . (**व्यवधान**) . . . एक मिनट, मैं अपनी बात पूरी कर लूंफिर जो भी

[श्री भजन लाल]

करेंगे वह भी मैं बताऊंगा ।... (व्यवधान)...

श्री राम अवधेश सिंह : मेरे सवाल का जवाब दीजिए । मैंने जो बिहार के बारे में पूछा था उसके बारे में बताइए आप ।... (व्यवधान)...

श्री भजन लाल : सुपर कम्प्यूटर के बारे में जैसा मैंने पहले कहा, 24 घंटे पहले बताता है, लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि 6-7 दिन पहले बताना चाहिए ताकि समय पर लोगों को पता लग जाए और नुकसान से लोग बच जाएं । केन्द्र सरकार की टीम शीघ्र भेजने की बात बिल्कुल ठीक है, शीघ्र भिजवाएंगे और मंत्री को भी दौरा करना चाहिए, ठीक सुझाव दिया अहलुवालिया ने । बिहार में बाढ़ का पानी निकालने का पूरा इंतजाम करेंगे । फसल बीमा के बारे में जैसा मैंने कहा फसल के बीमे का पैसा हम देंगे, जहां नुकसान हो गया है ।... (व्यवधान)...

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Sir, I would like to seek a clarification.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Let the hon. Minister finish.

श्री राम अवधेश सिंह : बिहार के बारे में स्पेसिफिक मैंने पूछा था कि हरियाणा के दो जिलों में बाढ़ आई तो 42 करोड़ रुपया दिया और 17 जिलों में बाढ़ आई बिहार में तो 14 करोड़ रुपया दिया गया, इसके बारे में जो... (व्यवधान)...

श्री मोर्जा इर्शादबेग : आपको यहां हाजिर होना चाहिए था । ... (व्यवधान)...

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Sir, I seek your protection.

श्री भजन लाल : आप जरा सुनने की कृपा करिए ।... (व्यवधान)... डा० रेड्डी ने एक बात कही यहां पर और सवाल दूसरा था, उनको यह प्वाइंट रेज नहीं करना चाहिए था कि श्रीलंका में करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, इसका क्या फायदा है और बाढ़ पर खर्च करते नहीं ? आप तो जानते हैं कि श्रीलंका पर जो खर्च किया गया है, कितनी मानव की सेवा की गई है । हिन्दुस्तान की, भारतवर्ष की एक प्रथा रही है, भारतवर्ष का इतिहास आपके सामने है कि जब भी किसी पर मुसीबत आती है तो भारतवर्ष उसकी सहायता पर पहले निकलता है । कभी का मिसाल उठाकर देख लीजिए, आज का नहीं है । जब लंका पर आप जानते हैं कि रामचन्द्र जी ने विजय हासिल की थी तो लंका का राज विभीषण को देकर आए थे । यह नहीं कि लंका पर कब्जा किया हो उन्होंने । ...(व्यवधान)...आप सुनने की कृपा करिए ।... (व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): That point was raised by Dr. Thulasi Reddy. The hon. Minister is answering that.

श्री भजन लाल : यह मानवता की रक्षा का सवाल है, । ...(व्यवधान)... अगर आपने रावण का हिमायती बनना है तो अलग बात है, मैं नहीं कह सकता । ...(व्यवधान) ...

श्री राम अवधेश सिंह : गए तमिल को बचाने और तमिल को लगे मारने । ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल : मर्यादा और मानवता का प्रतीक है भारतवर्ष .. (व्यवधान)... पाकिस्तान का जंग करके, बंगलादेश अलग बनाकर उनके हवाले किया, हिन्दुस्तान ने कब्जा नहीं किया । हिन्दुस्तान का इतिहास आपके सामने है । एक इतिहास नहीं है, सैकड़ों इतिहास आपको ऐसे मिलेंगे कि हिन्दुस्तान की क्या प्रथा है । आज हमारे युवा प्रधान मंत्री ने कितनी बड़ी बात की, उस देश के लोगों की रक्षा करने के लिए, आपको धन्यवाद करना चाहिए और आप कहते हैं कि इसकी क्या आवश्यकता थी ? इतने तमिल वहां मर रहे

है, आप इसको बर्दाश्त करते हैं ? कितनी ज्यादती, अन्याय तमिलों के साथ वहां हो रहा है, और वहां की सरकार ने, वहां के राष्ट्रपति ने बाकायदा लिखकर के भारत सरकार से सहायता मांगी, हमारे प्रधान मंत्री ने, तब हमने फौजें भेजीं और ऐसा नहीं कि हमने अचानक वहां पर फौज भेज दी, उनके मांगने पर... (व्यवधान)...तो थोड़ी सी समझने की कृपा करिए।...(व्यवधान)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Mr. Ram Awadhesh Singh. Kindly take your seat.

श्री वीरेन्द्र वर्मा : भई हो गया। ...(व्यवधान)...

श्री भजन लाल : एक आपने भेदभाव की फिर बात कह दी कि नहीं होना चाहिए, होने का सवाल ही नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा, प्रदेश का नाम लूंगा तो आपको तकलीफ होगी। आन्ध्र प्रदेश जिसने बहुत सी स्कीमों का नाम चेंज कर दिया। बाढ़ और सूखे के लिए जो पैसा दिया गया, आर० एल०ई०जी०पी० और एन० आर० ई० पी० का जो पैसा दिया गया उनका नाम बदल दिया आंध्र प्रदेश सरकार ने। हम आपको बताएंगे... (व्यवधान)...

6 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Please take your seat. Let the Msnister speak. Let him reply to your point.s (*Interruptions*). All the Members have raised points.

श्री भजन लाल : नुकसान के बारे में मैंने बताया कि बैंकों का कर्जा बहुत आसान किस्तों पर 20 साल में अदा होने वाले थोड़े ब्याज पर उनको दिलाएंगे... (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया : सी० ए० जी० ने लिखा है... (व्यवधान) सी. ए. जी. की रिपोर्ट पढ़ें (व्यवधान)

SHRI SUNIL BASU RAY: CAG report is against you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The Minister is replying. Why are you interfering?

श्री विट्ठलराव माधवराव जाधव (महाराष्ट्र) : रामाराव अकेले खा जाते हैं, इसलिए इनको गुस्सा आ रहा है... (व्यवधान)

श्री भजन लाल : उपसभाध्यक्ष महोदय, पवार साहब ने कहा कि सागर कन्या और मौसम विभाग का कृषि मंत्रालय में तालमेल होना चाहिए। तालमेल हम करते हैं, और ज्यादा इस पर जोर देंगे। राजस्थान में इन्होंने कहा कि वर्षा कम हुई है, लेकिन हमारी इत्तिला है कि कल परसों वह बहुत से एरियाज में वर्षा हो गई है। हो सकता है कि कुछ पाकेट्स रह गई हों जैसे हरियाणा और पंजाब में भी कुछ पाकेट्स रह गई हैं जहां वर्षा नहीं हुई।

जहां तक लोन का सवाल है जो नहीं दे सकेंगे उसको हम रिशैड्यूल करेंगे। एक स्कीम हम राष्ट्रीय लेवल की बना रहे हैं किसानों के हित में कि जहां पर लगातार तीन साल सूखा पड़ जाए या नुकसान हो जाए तो पहले साल का लोन ब्याज समेत माफ करेंगे, दूसरे साल का ब्याज माफ करेंगे और बाकायदा उसका रिशैड्यूल हो जाए ताकि किसानों को पूरी मदद मिल सके।

श्री धरम पाल जी ने कहा कि टीम को मैमोरंडम जल्दी भेजना चाहिए और जरूरतमंद को मदद मिलनी चाहिए। कुछ पैसा गलत तरीके से खर्च हो जाता है उसको हम चैक करेंगे। जिस काम के लिए मदद दी जाती है उसी काम में वह लगनी चाहिए। आपने कहा कि लोग ज्यादा मरे हैं पैसा थोड़ा दिया है। हम पूरी सहायता करेंगे। आपने कहा कि 10 हजार रुपए हर परिवार को दिए जाएंगे। जिस परिवार में लोग मरे हैं सबको 10 हजार रुपए प्रधान मंत्री कोष से दिए जाएंगे।

महोदय, इन शब्दों के साथ मैं सब माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं। कुछ बातें उन्होंने कहीं, आगे जानकारी जो

[श्री भजन लाल]

कुछ देनी होगी वह मैं देने की कोशिश करूंगा ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : माननीय मंत्री जी यह जानते हैं कि जितनी बाढ़ से क्षति होती है प्रतिवर्ष विभिन्न क्षेत्रों में उसमें जैसे अपने साधन हैं उसके अनुसार सरकार करने का प्रयास करती है । मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि प्रतिवर्ष एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की क्षति फसल की, मकानों की, सड़कों की, जानवरों की होती है । यह जो आप करते हैं यह अस्थायी व्यवस्था होती है । मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या भारत सरकार ने इसका कोई परमानेन्ट इलाज विशेषकर असम और बंगाल और उत्तरी बिहार जहां प्रतिवर्ष बाढ़ आती है, और जगहोंपर तो कभी-कभी आती है, वहां को परमानेन्ट इलाज करने के लिए कोई कमेटी बनायी है, कोई रिपोर्ट आयी है या करने का कोई विचार रखती है यह मैं आपसे जानना चाहता हूं ।

श्री भजन लाल : और कोई सदस्य प्रश्न पूछना चाहते हैं तो पूछ लें मैं एक साथ ही सबका जवाब दे दूंगा ।

श्री राम अवधेश सिंह: मैं यह जानना चाहता हूं कि जोफ्लड प्रोन एरियाज हैं जहां हर साल बाढ़ आती ही है उसमें उत्तर बिहार निश्चित रूप से है । वह हर साल बाढ़ का शिकार होता है तो क्या अभी इस साल सरकार के दिमाग में कोई योजना है, कोई बात है कि वह भार फ्लड से बचाने के लिए कुछ कर रही है; क्या ऐसा तो नहीं करेगी जैसा पिछले साल किया था कि हरियाणा के दो जिलों में बाढ़ आयी तो 42 करोड़ दे दिया और बिहार के 17 जिलों में बाढ़ आई तो 14 करोड़ दे दिया । क्या इसी तरीके से दिया जायेगा या कुछ नया तरीका निकाला जायेगा यह मैं जानना चाहता हूं ।

श्री नरेश सी० पुगलिया : उपसभाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का मैं बहुत आभारी हूं कि उन्होंने इस गम्भीर विषय पर जो मुद्दे माननीय सदस्यों ने उठाये थे उन पर अपने विचार रखे विस्तारपूर्वक । हम उम्मीद करते हैं कि जिन-जिन राज्यों में भारी नुकसान हुआ है वहां जल्दी मदद पहुंचायेंगे यह उन्होंने कहा है । मैं महाराष्ट्र के विषय में पूछना चाहता हूं कि आपकी सर्वे टीम जाने के पहले एडवांस में कोई राशि महाराष्ट्र में देने के लिए कृषि मंत्रालय की ओर से कोई कदम उठाया जा रहा है ? दूसरे मेरा सवाल यह है कि पिछले साल आपने बाढ़ के समय जितना पैसा राज्यों ने मांगा आपने दिया लेकिन कुछ राज्यों ने उसका दुरुपयोग किया है (**व्यवधान**) । सी. एंड. ए. जी. की रिपोर्ट में इस बारे में कहा गया है कि कुछ राज्यों ने जिनको बाढ़ की सहायता के लिए पैसा दिया गया था उन्होंने उसका सही इस्तेमाल नहीं किया और दूसरी जगह डाइवर्ट कर दिया । यह 25-6-89 के इंडियन एक्सप्रेस में भी आया है कि आंध्र प्रदेश को फ्लड रिलीफ के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो पैसा दिया गया था उस पैसे का उन्होंने मिसयूज किया है । (**व्यवधान**) मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय इसकी जांच करवायेंगे और उस पर उचित कार्रवाई करेंगे ?

श्री विठ्ठलराव माधवराव जाधव : मेरा सिर्फ एक प्रश्न है जो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं । उन्होंने बहुत जल्दी ध्यान देकर हमारे सदन का गौरव और प्रतिष्ठा बढ़ाई है । सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र में 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का नुकसान किसानों का और अन्य महाराष्ट्र के लोगों का हुआ है । यह भी बताया गया है 200 से 500 लोगों की जानें चली गयी हैं और इसके आंकड़े अभी आ रहे हैं । अभी पूरा पता नहीं लगा है । एक हजार से ज्यादा मछुआरों का पता नहीं है । इसके लिए अगर पैसा देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा । वैसे भारत सरकार अपनी पूरी ताकत के साथ रिलीफ काम के लिए कोशिश कर रही है । मुख्य मंत्री दो दिन से इधर-उधर घूमते फिरते हैं । हमने सुना है कि प्रधान मंत्री जी और हमारे भजन लाल जी तुरन्त वहां जा रहे हैं । मैं उनका अभिनन्दन करता हूं ।

मैं उनका सदन में अभिनन्दन करता हूं। जब जब भी नैसर्गिक आपत्ति आती है तो हमारे प्रधान मंत्री और हमारे मंत्री जल्दी से वहां जाते हैं और वहां लोगों को राहत देते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिए कितना पैसा दिया जा रहा हैं, यह बताने की कृपा की जाय।

श्री मीर्जा ईर्शादबेग: मैंने मंत्री जी से यह जानकारी चाही थी कि क्या उनको मवेशियों के बारे में जानकारी है? जहां तक मैं जानकारी रखता हूं, इस समय कोई स्पष्ट नियम नहीं बनाये गये हैं जिसमें उनकी सहायता की जा सके। जब इस प्रकार की आपत्ति आती है तो हजारों और लाखों की संख्या में हमारे पशुधन का विनाश हो जाता है। इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि इसके संदर्भ में क्या कोई आयोजन किया गया है और क्या कोई नये नियमों का प्रावधान किया गया है? दूसरी बात मैं गुजरात के संबंध में जानना चाहता हूं जिसका उल्लेख इसमें नहीं है, अखबारों में आया है कि जन हानि हुई है, इस बारे में क्या आपके पास कोई सूचना आई है? ये मेरे प्रश्न हैं जिनका उत्तर देने की कृपा की जाय।

श्री भजन लाल: उपसभाध्यक्ष महोदय, चार सदस्यों ने छोटे प्रश्न पूछे हैं। एक तो श्री वीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा कि असम, बंगाल और बिहार में हर साल बाढ़ आती है और इसलिए उसको रोकथाम के लिए क्या परमानेन्ट कदम उठाये गये हैं। मैं यह बताना चाहता हूं कि हमने असम को बार बार कहा है और खासतौर से ब्रहमपुत्र के संबंध में कहा है कि उसमें बहुत ज्यादा पानी आ जाता है और बारिश से उसके बांध टूट जाते हैं और उसकी वजह से ही विनाश होता है ... (**व्यवधान**)

श्री वीरेन्द्र वर्मा: जो नेशनल फ्लड कंट्रोल बोर्ड बना है उसने क्या कार्यवाही की है। असम सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है।

श्री भजन लाल: असम गवर्नमेंट को केन्द्रीय सरकार ने पैसा दिया। बाकायदा असम गवर्नमेंट को पिछले साल 85 करोड़ रुपये दिये गये जिसमें से 25 करोड़ रुपये उस काम पर लगायेंगे यानी ब्रह्मपुत्र के बैंकों को ठीक करने पर लगाने के लिए कहा गया, लेकिन वह पैसा भी ब्रह्मपुत्र पर नहीं लगाया गया। अगर वे बैंक ठीक किये जाते तो इतनी बाढ़ नहीं आती।

श्री राम अवधेश सिंह: श्रीमन्, मेरा पाइन्ट आफ आर्डर है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): There is no point of order. Kindly take your seat.

श्री राम अवधेश सिंह: मेरा पाइंट आफ आर्डर उनकी बात से उठता है।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): You have raised a question and the Minister is replying. Where is the point of order? There is no point of order. Kindly hear the Minister. Please take your seat... (*Interruptions*).

श्री राम अवधेश सिंह: मेरा पाइन्ट आफ आर्डर यह है कि ... (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN: Nothing will go on record.

SHRI MIRZA IRSHAD BAIG: Mr. Vice-Chairman, is it a point of order? It is a point of disorder.

... (*Interruptions*) ...

श्री राम अवधेश सिंह: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): This is not a point of order. Please take your seat.

श्री भजन लाल: बिहार के बारे में हमने पूरी सहायता की है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले साल 1987-88 में बकायदा 87 करोड़ रुपये बिहार को दिये गये।

*Not recorded.

श्री राम अवधेश सिंह : हरियाणा को दो जिलों के लिए 42 करोड़ रुपये दिये गये और बिहार के जब 17 जिले बाढ़ में डूब गये तो उसको 14 करोड़ रुपये दिये गये .. (व्यवधान)।

श्री भजन लाल : पिछले साल भूकम्प के लिए बिहार को 24.31 करोड़ रुपये दिये गये। भूकम्प की सहायता के लिये दिये गये।

श्री राम अवधेश सिंह : मैं भूकम्प की बात नहीं पूछ रहा हूं।

श्री भजन लाल : यह बात आप श्री देवी लाल से पूछिये। वे कहते हैं कि कम दिया गया और आप कहते हैं कि ज्यादा दिया गया है .... (व्यवधान)

श्री मीर्जा इर्शादबेग : वहां पर जो टीम गई उसने जायजा लिया .. (व्यवधान)

श्री भजन लाल : बाकायदा उसके ऊपर फैसला लिया गया। ... (व्यवधान) ...

जहां तक पैसे का मिस यूज करने का सवाल है .. (व्यवधान) ..

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Ram Awadhesh Ji, you have raised your point. When the Minister is replying, you kindly hear him. Why are you interfering in the middle?

SHRI RAM AWADHESH SINGH: Why shouldn't I interfere? I must interfere.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): When the Minister is replying, without hearing the Minister, why are you interfering?

SHRI RAM AWADHESH SINGH: He cannot be allowed to give wrong information to the House.

श्री भजन लाल : इनका क्वेश्चन क्या है ...

श्री वीरेन्द्र वर्मा : मेरे सवाल का क्या जवाब दिया ?

श्री भजन लाल : आप जवाब सुनते ही नहीं। बाकायदा अभी मैंने उसके बारे में बताया।

श्री वीरेन्द्र वर्मा : क्या बताया ?

श्री भजन लाल : आपकी समझ में नहीं आया तो मैं क्या करूं। ... (व्यवधान) ..

जहां तक पैसे का मिस यूज करने का ताल्लुक है मैं यह कहना चाहूंगा कि हम जांच करेंगे।

श्री राम अवधेश सिंह : बिहार को बाढ़ से बचने के लिये भारत सरकार क्या कर रही है ?

श्री भजन लाल : वहां पर अपोजीशन की सरकार है। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह इंडियन एक्सप्रेस में है। यहां पर खास करके अपोजीशन की हथियार है अगर मैं यह कहूं तो यह गलत न होगा कि अपोजीशन का वह पेपर इश्तिहार है, अपोजीशन की सरकार के बारे में ? वह कहता है कि बाकायदा जो पैसा फ्लड के लिये दिया गया आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने उसका मिस-यूज किया है यह सी०ए०जी० रिपोर्ट है जिसको लेकर आपने बावेला मचा रखा है। यह रिपोर्ट यह कहती है।

SHRI MIRZA IRSHADBAIG: Mr. Satyanarayan Reddy, this is the CAG Report. (*Interruptions*)

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: There was no misuse.

श्री भजन लाल : यह रिपोर्ट कहती है। ... (व्यवधान) ...

श्री वी. सत्यनारायण रेड्डी : यह हरियाणा नहीं है ... (व्यवधान) ...

श्री भजन लाल: यह मैं आपको भेज रहा हूं। इसे मैं टेबल पर रखता हूं। आप इसको पढ़ लीजिये ... (**व्यवधान**)... इसे मैं टेबल पर रखता हूं। मैं इसको आपके पास भेज देता हूं। यह आप पढ़ लीजिये। यह इंडियन एक्सप्रेस में है। यह मैं नहीं कह रहा हूं ...(**व्यवधान**)...सी.ए.जी. रिपोर्ट पढ़ लीजिए। यह वैसे नहीं कह रहा हूं।

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी: जनता रिजीम में...(**व्यवधान**)...

श्री भजन लाल: सी.ए.जी. रिपोर्ट देख लीजिये मैं आपको कहता हूं... (**व्यवधान**)...

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी: आपने लोगों के साथ जो ...(**व्यवधान**)...

आपको मंत्री बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।

श्री भजन लाल: रेड्डी साहब सुनियेगा। मैं आपको...(**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): The Minister has gone to the other point. You kindly sit down.

श्री भजन लाल: आप किसकी बात कर रहे हैं। आप जिसको लीडर मानते हैं उसका क्या किरदार है? कैसे बातें करते हैं। आपको पता है जिसके खिलाफ कोर्ट ने फैसला दे रखा हो उसके बारे में आप क्या कहते हैं? विश्वामित्र बने बैठे हैं...(**व्यवधान**).. किसकी बात करते हैं आप? थोड़ी बहुत सोच कर बात करनी चाहिये। क्या बात करते हैं। आपकी हम इज्जत करते हैं आपको तकलीफ तो होगी। लेकिन यह सत्य है एक परसेंट भी गलत नहीं है. इस बात का मैं चैलेंज करता हूं। (**व्यवधान**) उनके पास कागज है मैंने दिया है (**व्यवधान**) मेरा चैलेंज खड़ा रहेगा आपके सामने (**व्यवधान**)

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI V. NARAYANASAMY): Kindly take your seats. I am on my legs. (*Interruption*).. The Minister has gone to another point. Please take your seats. (*Interruptions*)..

श्री बी० सत्यनारायण रेड्डी: भजन लाल जी आपको जवाब देना पड़ेगा (**व्यवधान**) जब आप मुख्य मन्त्री थे हरियाणा में जनता रिजीम में (**व्यवधान**) आपने धोखा दिया (**व्यवधान**) देश को धोखा दिया (**व्यवधान**)

श्री भजन लाल: आप उसको धोखा कहते हैं (**व्यवधान**) मैं जवाब देता हूं आप पूछिये (**व्यवधान**) आपने यह कहा कि (**व्यवधान**)

श्री सुरेन्द्रजीत सिंह अहलुवालिया: केन्द्र से जो लिया लोगों को (**व्यवधान**) एअर कंडीशनर खरीदे गये (**व्यवधान**) सोफा सेट खरीदे गये (**व्यवधान**)

श्री बी० सत्यनरायण रेड्डी: धोखा दिया है (**व्यवधान**)

श्री भजन लाल: मैं जवाब देता हूं (**व्यवधान**) आप कृपा कर के सुनिये (**व्यवधान**) आपने मुझे कहा है कि मैंने एक बार दल बदला, एक बार इधर से उधर चला गया (**व्यवधान**) मैंने कभी धोखा नहीं किया और न धोखा देकर (**व्यवधान**) जिसको आप लीडर मानते हो देवी लाल को इस ने 21 बार पार्टी बदली और आप सैकेंड लीडर चौधरी चरण सिंह को मानते हो उसने 19 बार पार्टी बदली कुर्सी के लिए। किस की बात करते हो आप लोग (**व्यवधान**) क्या किरदार है एन० टी० आर० का (**व्यवधान**)

श्री बी. सत्यनारायण रेड्डी: धोखा दिया है (**व्यवधान**)

श्री भजन लाल: धोखा और विश्वास-घात तो आप करते हैं (**व्यवधान**) आप लोग एक रुपया साठ पैसे चावल ले कर दो रुपये में बेचते हैं। एक रुपया साठ पैसे भारत सरकार दे (**व्यवधान**) और दो रुपये में बेचते हैं।

SHRI S. S. AHLUWALIA: We are ready to discuss CAG's report on Andhra Pradesh...(*Interruption*)...

DR. YELAMANCHILI SIVAJI: I am on a point of order...(*Interruption*)...

श्री भजन लाल : गुजरात राज्य के बारे में हमारे पास सूचना आ गई है। जूनागढ़, भड़ौच और कच्छ जिलों में कुल मिला कर तीन लोगों की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मरने वालों की संख्या जो मैंने पहले 586 बताई थी अब 589 हो गई है। धन्यवाद।

EMPLOYEES' STATE INSURANCE (AMENDMENT) BILL, 1989

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI BINDESHWARI DUBEY): Sir, I beg to move:

"That the Bill further to amend the Employees' State Insurance Act, 1948, be taken into consideration."

Sir, as the hon. Members are aware, the Employees' State Insurance Act 1948 provides inter alia for grant of cash benefit to the employees in the event of sickness, maternity and employment injury. In addition, medical care is provided to the insured persons and his or her family. The Act which is applicable, in the first instance, to non-seasonal factories employing 20 or more persons and using power in manufacturing processes is now being gradually extended areawise to certain new classes of establishments in a phased manner. As on 31st December 1988, the Act covered about 61.68 lakh workers and 580 industrial centres in the country. The total number of beneficiaries including the family members for medical care was 2.73 crores. The Employees' State Insurance Act was last amended in 1984. One of the major amendments carried out at that time related to raising the wage limit for coverage of workers from Rs. 1,000 to Rs. 1,600 per month. However, with the increase in wages, the workers have again started going out of the coverage and it has become necessary to further increase the wage limit for coverage of the workers.

There are certain other provisions such as those relating to wage limits for exemption of employees from payment of employees' contribution which requires treble enhancement. Similarly, the rates of various benefits may also have to be periodically enhanced to compensate for rise in cost of living. At present, all these provisions are governed by specific provisions of the Act. Any change in these provisions requires amendment of the Act which ly takes time. It is, therefore, now proposed to provide for prescribing all these matters in the rules so that necessary changes may be effected as and when necessary. The copies of the notifications carrying out amendments in the rules would however, be laid before the Parliament as provided in the Act.

There are two amendments which are of particular interest to the workers. The first of these amendments relates to inclusion of all the children of the insured persons up to the age of 21 years and infirm children without any age restriction in the definition of family so as to make them eligible for the medical benefits under the Act. At present, medical benefits are available only to minor children, that is, children up to the age of 18 years. The second amendment seeks to provide for continuance of medical benefits to the insured persons who have to leave insurable employment due to employment injury and retired insured persons and their spouses subject to payment of contributions. At present, medical benefits are available to insured persons only so long as they are in insurable employment.

An important aspect of the administration of the ESI scheme relates to the autonomy of the ESI Corporation which is self-financing. The members of the ESI Corporation, particularly the representatives of the employers and employees, have been pleading for greater autonomy and freedom of action for the Corporation. Considering the number of persons who contribute to the scheme and the vast amount of funds handled a certain measure of Government control seems to be unavoidable. However, any rigid control of the organisation with a view to safeguarding the funds and the interests of the